IUC ACADEMY
INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY
Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

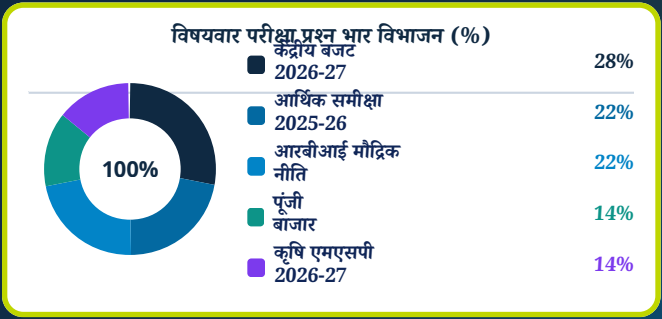
IUC अध्ययन सामग्री

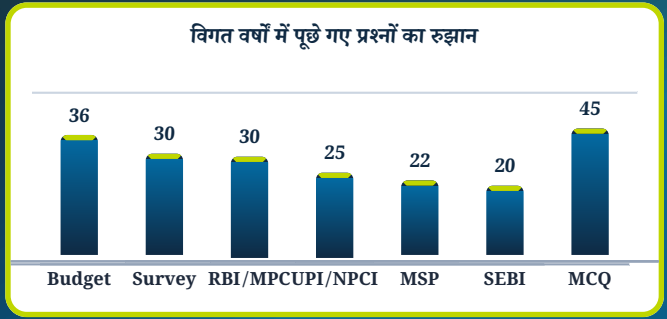
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

समसामयिकी 2026 — भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, आरबीआई एवं केंद्रीय बजट 2026-27

CURRENT AFFAIRS 2026 — INDIAN ECONOMY, BANKING, RBI & UNION BUDGET 2026-27

केंद्रीय बजट 2026-27 (₹53.47 लाख करोड़) एवं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संपूर्ण आँकड़े, राजकोषीय घाटा (4.3%), आरबीआई मौद्रिक नीति 2026, यूपीआई वैश्विक विस्तार, सेबी सुधार, महारत्न/नवरत्न कंपनियाँ, कृषि एमएसपी एवं विदेशी व्यापार





लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ

UPSC CSE • State PCS • RBI Grade B • IBPS/SBI PO & Clerk • SSC • UPSC EPFO • NABARD • JAIIB/CAIIB

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- केंद्रीय बजट 2026-27, कर सुधार, राजकोषीय घाटा एवं मंत्रालय आवंटन (28%)
- आर्थिक समीक्षा 2025-26, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं रोजगार (22%)
- आरबीआई मौद्रिक नीति 2026, एनपीसीआई (UPI) एवं डिजिटल बैंकिंग (22%)
- पूंजी बाजार (SEBI सुधार), जीएसटी परिषद निर्णय एवं पीएलआई योजना (14%)
- कृषि एमएसपी 2026-27, विदेशी मुद्रा भंडार एवं बाह्य व्यापार (14%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित पुनरावलोकन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — समसामयिकी 2026 — भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, आरबीआई एवं केंद्रीय बजट 2026-27

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन सामग्री

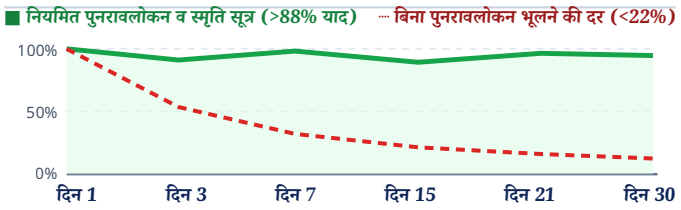
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मरण सूत्र** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

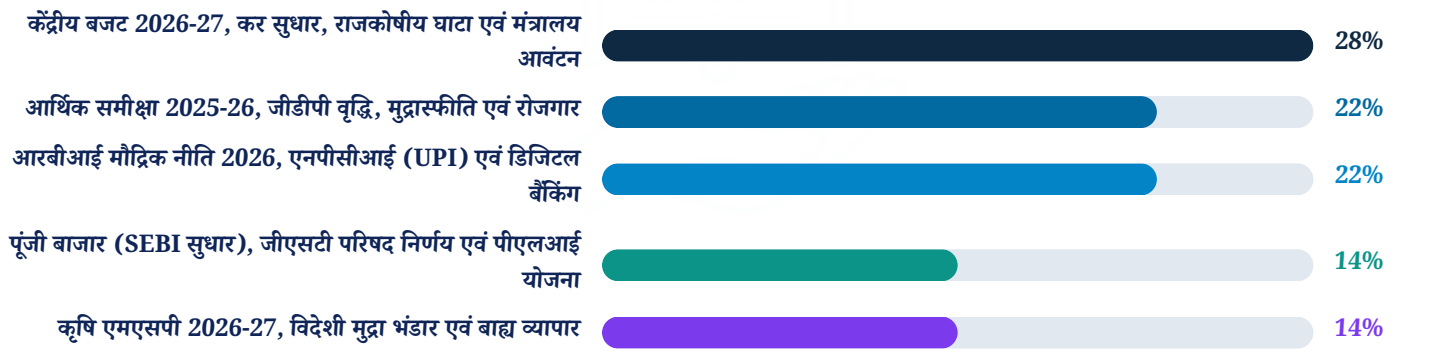
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित पुनरावलोकन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार परीक्षा प्रश्न भार सूचकांक (%)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत

- केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल (https://www.indiabudget.gov.in/)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) (https://www.rbi.org.in/)
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (https://www.sebi.gov.in/)
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) (https://www.npci.org.in/)
- IUC अकादमी आधिकारिक पोर्टल (https://www.iucacademy.com)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना

समसामयिकी 2026 — भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, आरबीआई एवं केंद्रीय बजट 2026-27 • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित पुनरावलोकन

1. अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 — संपूर्ण राजकोषीय वास्तुकला, घाटे के संकेतक एवं ऋण समेकन पथ

- 1.1 केंद्रीय बजट 2026–27 (बजट अनुमान 2026–27) एवं संशोधित अनुमान 2025–26 (संशोधित अनुमान 2025–26) के प्रमुख राजकोषीय आँकड़े
- 1.2 राजकोषीय घाटा और नया 'ऋण-जीडीपी समेकन पथ' (--जीडीपी 2026–2031)
- 1.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत का राजकोषीय समेकन एवं ऋण-जीडीपी ग्लाइड पाथ (वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष31)
- 1.4 तुलनात्मक सारणी: केंद्रीय बजट 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 के आधिकारिक राजकोषीय संकेतक

2. अध्याय 2: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 — वास्तविक जीडीपी वृद्धि परिदृश्य (6.8%–7.2%), क्षेत्रीय जीवीए, प्रभावी पूँजीगत व्यय एवं विकसित भारत @ 2047

- 2.1 आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के वृहद-आर्थिक निष्कर्ष एवं जीडीपी वृद्धि अनुमान
- 2.2 क्षेत्रीय प्रदर्शन (कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र), मुद्रास्फीति एवं रोजगार सृजन रणनीति
- 2.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 का 'पूँजीगत व्यय से सतत आर्थिक वृद्धि' संचरण तंत्र
- 2.4 तुलनात्मक सारणी: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के प्रमुख वृहद-आर्थिक संकेतक एवं संरचनात्मक रुझान

3. अध्याय 3: केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार — अंश पुनर्खरीद, न्यूनतम वैकल्पिक कर, सीमा शुल्क युक्तिकरण एवं 16वाँ वित्त आयोग हस्तांतरण सूत्र

- 3.1 प्रत्यक्ष कर सुधार (कर): शेयर बायबैक कराधान, न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं विवाद समाधान
- 3.2 अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सुधार: 17 कैंसर दवाओं पर छूट एवं कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली)
- 3.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बजट 2026–27 के कर सुधार एवं 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र
- 3.4 तुलनात्मक सारणी: केंद्रीय बजट (2026 संकलन) के प्रमुख कर और राजकोषीय सुधार प्रावधान

4. अध्याय 4: भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति 2026 — गवर्नर संजय मल्होत्रा के नीतिगत निर्णय, 5.50% रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात कटौती एवं तरलता प्रबंधन

- 4.1 आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति) एवं 2025–2026 के प्रमुख नीतिगत निर्णय
- 4.2 तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा), एसडीएफ (स्थायी जमा सुविधा), वीआरआरआर (परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो) एवं एचटीएम (परिपक्वता तक धारित) पोर्टफोलियो नियम
- 4.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आरबीआई का तरलता प्रबंधन एवं मौद्रिक नीति संचरण तंत्र (2026 संकलन)
- 4.4 तुलनात्मक सारणी: आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण, आरक्षित अनुपात एवं नियामक निर्देश (2026 संकलन)

5. अध्याय 5: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग मानदंड, बेसल मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं आरबीआई डिजिटल मंच

- 5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए इंटरनेट बैंकिंग पात्रता मानदंडों में संशोधन एवं बैंकिंग सुदृढ़ता
- 5.2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निदेश 2025, बेसल- मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं प्रमुख आरबीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म
- 5.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) को इंटरनेट बैंकिंग अनुमति मिलने का संशोधित नियामक चक्र
- 5.4 तुलनात्मक सारणी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) इंटरनेट बैंकिंग मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य एवं प्रमुख आरबीआई पोर्टल

6. अध्याय 6: डिजिटल भुगतान क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के 2026 परिपत्र, यूपीआई लाइट, यूपीआई सर्कल, व्यापार सक्षम एवं डिजिटल रुपया

- 6.1 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और यूपीआई (यूपीआई) पारिस्थितिकी तंत्र के नवीनतम नवाचार (2026 संकलन)
- 6.2 उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई विस्तार एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी / -)
- 6.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: एनपीसीआई के आधुनिक यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र (यूपीआई , यूपीआई सर्कल व यूपीआई) की कार्यप्रणाली
- 6.4 तुलनात्मक सारणी: एनपीसीआई के प्रमुख डिजिटल भुगतान उत्पाद, सीमाएँ एवं 2025–2026 के नवीनतम परिपत्र

7. अध्याय 7: वस्तु एवं सेवा कर वास्तुकला, 56वीं एवं 57वीं जीएसटी परिषद बैठक (अक्टूबर 2026) के निर्णय, अपीलीय न्यायाधिकरण एवं धारा 128क समाधान योजना

- 7.1 जीएसटी संवैधानिक ढाँचा (101वाँ संशोधन) एवं जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क) की मतदान संरचना
- 7.2 हालिया जीएसटी परिषद बैठकों (53वीं–55वीं) के प्रमुख निर्णय, धारा 128क माफी योजना एवं जीसैट (जीएसटी)
- 7.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: जीएसटी विवाद निवारण एवं अपीलीय पदानुक्रम (जीएसटी एवं नई मौद्रिक सीमाएँ)
- 7.4 तुलनात्मक सारणी: जीएसटी संवैधानिक प्रावधान, अपीलीय सीमाएँ एवं हालिया जीएसटी परिषद सुधार

8. अध्याय 8: वित्तीय एवं पूँजी बाजार (सेबी सुधार 2026) तथा भारत का बाह्य क्षेत्र — 22.2 करोड़ डीमैट खाते, दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध, 734.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार एवं हरितक्षेत्र विदेशी निवेश

- 8.1 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नवीनतम पूँजी बाजार सुधार एवं आँकड़े (2026 संकलन)
- 8.2 भारत का बाह्य क्षेत्र — 734.6 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व में तीसरा स्थान एवं प्रवासी जमा
- 8.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत के पूँजी बाजार एवं बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ीकरण का समग्र चक्र (2026 संकलन)
- 8.4 तुलनात्मक सारणी: सेबी (सेबी) पूँजी बाजार आँकड़े एवं आरबीआई (आरबीआई) बाह्य क्षेत्र संकेतक (2026 संकलन)
- 8.5 विशेष परिशिष्ट: संवैधानिक-आर्थिक अंतर्संबंध एवं अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा (अनुसूचित जाति//अनुसूचित जाति/) उच्च-प्राथमिकता विश्लेषण (2026 संकलन)
- 8.7 समग्र विश्लेषणात्मक सार-संग्रह: वर्ष 2026 के संवैधानिक, न्यायिक, विधायी एवं राजकोषीय मानक

9. हल सहित बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न (45 हल सहित अभ्यास प्रश्न — द्वितीय खंड)

10. त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 त्वरित पुनरावलोकन बिंदु — द्वितीय खंड)

- 8.6 परीक्षा-उन्मुख समेकित संदर्भ सारणी: प्रमुख आर्थिक एवं राजव्यवस्था योजनाएँ, आयोग एवं वैश्विक वित्तीय संस्थान (2026 संकलन)

11. व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

- बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

12. अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अध्ययन अध्ययन इकाई पोर्टल: आईयूसी अकादमी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग अध्ययन केंद्र | **आधिकारिक संदर्भ:** केंद्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण पोर्टल | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) | भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 — संपूर्ण राजकोषीय वास्तुकला, घाटे के संकेतक एवं ऋण समेकन पथ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 1: केंद्रीय बजट 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 — संपूर्ण राजकोषीय वास्तुकला, घाटे के संकेतक एवं ऋण समेकन पथ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
केंद्रीय बजट 2026–27 (बजट अनुमान 2026–27) एवं संशोधित अनुमान 2025–26 (संशोधित अनुमान 2025–26) के प्रमुख राजकोषीय आँकड़े	राजकोषीय घाटा और नया 'ऋण-जीडीपी समेकन पथ' (--जीडीपी 2026–2031)	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत का राजकोषीय समेकन एवं ऋण-जीडीपी ग्लाइड पाथ (वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष31)

1.1 केंद्रीय बजट 2026–27 (बजट अनुमान 2026–27) एवं संशोधित अनुमान 2025–26 (संशोधित अनुमान 2025–26) के प्रमुख राजकोषीय आँकड़े

• **संवैधानिक आधार एवं प्रस्तुति:** संविधान के **अनुच्छेद 112** ('वार्षिक वित्तीय विवरण' —) के अंतर्गत केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री **निर्मला सीतारमण** द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में **केंद्रीय बजट 2026–27** प्रस्तुत किया गया। यह बजट **16वें वित्त आयोग** की पाँच-वर्षीय पंचाट अवधि (2026–2031) के प्रथम वर्ष का बजट भी है (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

• **कुल व्यय एवं पूँजीगत व्यय:**

1. **बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में कुल व्यय:** केंद्र सरकार का कुल व्यय **₹53.47 लाख करोड़** (सकल घरेलू उत्पाद का **13.6 प्रतिशत**) अनुमानित है, जो संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 के **₹49.65 लाख करोड़** (लगभग ₹49.6 लाख करोड़) की तुलना में 7.7 **प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

2. **पूँजीगत व्यय और राज्यों को विशेष सहायता (अनुसूचित जाति):** संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 में केंद्र का पूँजीगत व्यय लगभग **₹11 लाख करोड़** रहा, जबकि बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में पूँजीगत व्यय के लिए जीडीपी के **3.1 प्रतिशत** का प्रावधान किया गया है। इसमें **'पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता' (अनुसूचित जाति —)** के तहत राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में **₹2.0 लाख करोड़** का परिव्यय शामिल है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

• **कुल प्राप्तियाँ, कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व (बजट अनुमान 2026–27 बनाम संशोधित अनुमान 2025–26):**

1. **संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 में प्राप्तियाँ:** उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ **₹34 लाख करोड़** रहीं, जिनमें केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (' कर) **₹26.7 लाख करोड़** रहा (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

2. **बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ):** संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ **₹35.33 लाख करोड़** अनुमानित हैं (संशोधित अनुमान 2025–26 की तुलना में **5.7% की वृद्धि**), जिसके दो मुख्य घटक हैं — केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व (कर) **₹28.67 लाख करोड़** तथा गैर-कर राजस्व (-कर — आरबीआई व सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश सहित) **₹6.66 लाख करोड़**। इसके अतिरिक्त, ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ (- — ऋणों की वसूली एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ) **₹1.18 लाख करोड़** अनुमानित हैं। सकल अप्रत्यक्ष कर संग्रह **₹17.07 लाख करोड़** अनुमानित है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

1.2 राजकोषीय घाटा और नया 'ऋण-जीडीपी समेकन पथ' (--जीडीपी 2026–2031)

• **राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की प्रतिबद्धता की पूर्ति (4.4% से 4.3%):** वित्त मंत्री ने वर्ष 2021–22 के बजट में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वित्त वर्ष 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के **4.5 प्रतिशत से नीचे** लाया जाएगा। सरकार ने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करते हुए **संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 प्रतिशत** पर रखा (जो वित्त वर्ष 2020–21 के 9.2% और वित्त वर्ष 2021–22 के 6.7% से घटकर आधे से भी कम हो गया है) तथा **बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत** निर्धारित किया है (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

• **नया राजकोषीय एंकर — केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी : 50±1% 2030–31):** वित्त वर्ष 2026–27 से राजकोषीय प्रबंधन का मुख्य परिचालन लक्ष्य वार्षिक राजकोषीय घाटे के साथ-साथ **'केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात' (--जीडीपी)** को निरंतर घटाते जाने के पथ पर केंद्रित किया गया है:

1. **वर्ष 2030–31 का दीर्घकालिक लक्ष्य:** केंद्र सरकार ने **वित्त वर्ष 2030–31 (31 मार्च 2031) तक केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात को घटाकर जीडीपी के 50± 1 प्रतिशत** पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

2. **2025–26 और 2026–27 के ऋण आँकड़े:** केंद्र सरकार का कुल ऋण-जीडीपी अनुपात **संशोधित अनुमान 2025–26 के 56.1 प्रतिशत** से घटकर **बजट अनुमान 2026–27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत** रहने का अनुमान है (यदि राष्ट्रीय लघु बचत कोष के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश की देनदारियों — जो संशोधित अनुमान 2025–26 में 0.7% और बजट अनुमान 2026–27 में 0.5% हैं — को घटा दिया जाए, तो केंद्र का शुद्ध ऋण अनुपात संशोधित अनुमान 2025–26 में **55.5%** और बजट अनुमान 2026–27 में **55.1%** बैठता है) (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

1.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत का राजकोषीय समेकन एवं ऋण-जीडीपी ग्लाइड पाथ (वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष31)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: महामारी-कालीन राजकोषीय शिखर (वित्त वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा 9.2% और वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7%) से क्रमिक राजस्व सुदृढ़ीकरण

चरण 2
चरण 2: संशोधित अनुमान 2025–26 में 4.5% से नीचे के लक्ष्य की प्राप्ति — राजकोषीय घाटा 4.4% एवं ऋण-जीडीपी अनुपात 56.1%

चरण 3
चरण 3: बजट अनुमान 2026–27 में ₹53.47 लाख करोड़ के कुल व्यय के साथ राजकोषीय घाटा 4.3% एवं ऋण-जीडीपी अनुपात 55.6%

चरण 4
चरण 4: नए राजकोषीय समेकन पथ के तहत वर्ष 2030–31 तक केंद्रीय ऋण-जीडीपी अनुपात को 50±1% पर लाने का लक्ष्य]`

1.4 तुलनात्मक सारणी: केंद्रीय बजट 2026–27 एवं संशोधित अनुमान 2025–26 के आधिकारिक राजकोषीय संकेतक

राजकोषीय संकेतक / बजट मद	संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26	बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27	मुख्य विशेषता / जीडीपी का प्रतिशत / वृद्धि दर	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
कुल व्यय	**₹49.65 लाख करोड़** (~₹49.6 लाख करोड़)	**₹53.47 लाख करोड़**	बजट अनुमान 2026–27 में जीडीपी का **13.6%** (संशोधित अनुमान 2025–26 पर **7.7% वृद्धि**)	राजकोषीय नीति विवरण
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)	₹33.42 लाख करोड़ (आधार)	**₹35.33 लाख करोड़**	संशोधित अनुमान 2025–26 की तुलना में **5.7% की वृद्धि** अनुमानित	राजकोषीय नीति विवरण
शुद्ध कर राजस्व (कर)	**₹26.7 लाख करोड़**	**₹28.67 लाख करोड़**	16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को **41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण** के पश्चात्	केंद्रीय बजट भाषण 2026–27
गैर-कर राजस्व (-कर —)	—	**₹6.66 लाख करोड़**	आरबीआई अधिशेष हस्तांतरण, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश व स्पेक्ट्रम शुल्क शामिल	राजकोषीय नीति विवरण
ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ	—	**₹1.18 लाख करोड़**	ऋणों व अग्रिमों की वसूली तथा विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	राजकोषीय नीति विवरण
राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति)	राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम	**₹2.0 लाख करोड़**	50-वर्षीय ब्याज-मुक्त पूँजीगत ऋण; केंद्रीय कैपेक्स जीडीपी का **3.1%**	राजकोषीय नीति विवरण
राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी)	**4.4% (जीडीपी का)**	**4.3% (जीडीपी का)**	वित्त वर्ष 2020–21 के 9.2% से घटाकर आधे से भी कम किया गया	केंद्रीय बजट भाषण 2026–27
केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी)	**56.1% (जीडीपी का)**	**55.6% (जीडीपी का)**	वर्ष **2030–31 तक 50± 1%** तक घटाने का दीर्घकालिक लक्ष्य	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु

क्या आप जानते हैं?: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत वित्त मंत्री को प्रत्येक वर्ष बजट के साथ संसद के समक्ष **तीन अनिवार्य नीतिगत विवरण** प्रस्तुत करने होते हैं: **मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण (रूपरेखा)**, और मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण (राजकोषीय नीति विवरण)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर **'प्रभावी पूँजीगत व्यय'** और **'प्रत्यक्ष पूँजीगत व्यय'** के बीच अंतर पूछा जाता है: याद रखें कि **प्रभावी पूँजीगत व्यय = केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष पूँजीगत व्यय + पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान**। हालाँकि सहायता अनुदान बजट लेखांकन में 'राजस्व व्यय' के अंतर्गत आते हैं, किंतु चूँकि उनसे स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, इसलिए उन्हें प्रभावी पूँजीगत व्यय में जोड़ा जाता है (जो वित्त वर्ष 2026 संकलन–25–26 में बढ़कर जीडीपी के **4 प्रतिशत** के स्तर पर पहुँच गया है) (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।

★ **स्मरण सूत्र:** केंद्रीय बजट 2026–27 के 5 सबसे महत्वपूर्ण आँकड़े याद रखने का सूत्र — **"कुल खर्च 53.47 लाख करोड़, राजस्व प्राप्ति 35.33 लाख करोड़ (शुद्ध कर 28.67 + गैर-कर 6.66), राज्यों को अनुसूचित जाति कैपेक्स ऋण 2.0 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 4.4% से घटकर 4.3%, और ऋण-जीडीपी 56.1% से घटकर 55.6% (लक्ष्य 2030-31 तक 50±1%)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 2: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 — वास्तविक जीडीपी वृद्धि परिदृश्य (6.8%–7.2%), क्षेत्रीय जीवीए, प्रभावी पूँजीगत व्यय एवं विकसित भारत @ 2047

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 — वास्तविक जीडीपी वृद्धि परिदृश्य (6.8%–7.2%), क्षेत्रीय जीवीए, प्रभावी पूँजीगत व्यय एवं विकसित भारत @ 2047

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के वृहद-आर्थिक निष्कर्ष एवं जीडीपी वृद्धि अनुमान	**क्षेत्रीय प्रदर्शन (कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र), मुद्रास्फीति एवं रोजगार सृजन रणनीति**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 का 'पूँजीगत व्यय से सतत आर्थिक वृद्धि' संचरण तंत्र**

2.1 आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के वृहद-आर्थिक निष्कर्ष एवं जीडीपी वृद्धि अनुमान

• **वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (जीडीपी : 6.8% से 7.2%):** मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 (2025–26)** के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, विश्व भर में बढ़ते संप्रभु बॉन्ड प्रतिफल और बिगड़ते प्राथमिक संतुलन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूत वृद्धि गति को बनाए रखा है और **वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत (6.8% – 7.2%)** के बीच रहने का अनुमान है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

• **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के मुख्य विषयगत अध्याय:** आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने अपनी संरचना को मुख्य अध्यायों में विभाजित किया है जिनमें प्रमुख हैं: अर्थव्यवस्था की स्थिति: वृद्धि के क्षितिज का विस्तार; राजकोषीय विकास: विश्वसनीय समेकन के माध्यम से स्थिरता को आधार देना; तथा मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय मध्यस्थता, बाह्य क्षेत्र संतुलन और उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान कर कार्यशील पूँजी में सुधार (आर्थिक सर्वेक्षण पोर्टल)।

• **सार्वजनिक पूँजीगत व्यय का विस्तार (प्रभावी पूँजीगत व्यय & अनुसूचित जाति):** आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 रेखांकित करता है कि:

1. केंद्र सरकार का **प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय--जीडीपी)** महामारी-पूर्व के **2.7 प्रतिशत के औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) में जीडीपी के 4 प्रतिशत** तक पहुँच गया (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

2. केंद्र की **अनुसूचित जाति योजना** ने राज्यों को अपने पूँजीगत व्यय को **जीडीपी के 2.4 प्रतिशत** के उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

3. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 (वित्त वर्ष 2020–21) के **9.2 प्रतिशत** के राजकोषीय घाटे को घटाकर आधे से भी कम कर दिया (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 में 4.8% और संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2025–26 में 4.4% का लक्ष्य प्राप्त किया) (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 अध्याय)।

2.2 क्षेत्रीय प्रदर्शन (कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र), मुद्रास्फीति एवं रोजगार सृजन रणनीति

• **तीन क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए):** भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में **सेवा क्षेत्र** लगभग 54–55% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा इंजन बना हुआ है (जिसमें वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट, आईटी-बीपीएम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की प्रमुख भूमिका है); **उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र** लगभग 27–28% का योगदान देता है (जिसे 14 क्षेत्रों की योजनाओं, सेमीकंडक्टर मिशन और उच्च पूँजीगत व्यय से गति मिली है); जबकि **कृषि और संबद्ध क्षेत्र** देश के लगभग 45.8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करते हुए जीवीए में लगभग 17–18% का योगदान देता है और ग्रामीण माँग को आधार प्रदान करता है (आर्थिक सर्वेक्षण पोर्टल)।

• **बाह्य संतुलन में सुधार और चालू खाता घाटा (/जीडीपी):** सेवा निर्यात के रिकॉर्ड अधिशेष और विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तियों के बल पर भारत का **चालू खाता घाटा** जीडीपी के अत्यंत प्रबंधनीय दायरे (लगभग 1% के आसपास) में बना रहा है, जिससे बाह्य क्षेत्र का संतुलन मजबूत हुआ है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

• **मध्यम-अवधि वृद्धि रणनीति — विनियमन मुक्ति, सशक्तीकरण एवं कौशल विकास:** आर्थिक सर्वेक्षण ने मध्यम अवधि में 7%+ की सतत वृद्धि दर बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों पर बल दिया है: भूमि, श्रम और भवन निर्माण नियमों का राज्य-स्तरीय सरलीकरण व विनियमन मुक्ति; **उल्टे शुल्क ढाँचे (— जहाँ तैयार माल की तुलना में कच्चे माल या मध्यवर्ती इनपुट पर अधिक सीमा शुल्क लगता है)** को समाप्त कर घरेलू विनिर्माण की कार्यशील पूँजी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना; तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के युग में युवाओं का कौशल उन्नयन और निजी क्षेत्र के पूँजीगत निवेश (पूँजीगत व्यय) को गति देना (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

2.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 का 'पूँजीगत व्यय से सतत आर्थिक वृद्धि' संचरण तंत्र

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: केंद्र के प्रभावी कैपेक्स का जीडीपी के 4% तक विस्तार एवं अनुसूचित जाति के माध्यम से राज्यों के 2.4% कैपेक्स को प्रोत्साहन

चरण 2
चरण 2: भौतिक व डिजिटल अवसंरचना निर्माण तथा उल्टे शुल्क ढाँचे के सुधार से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

चरण 3
चरण 3: निजी कॉर्पोरेट निवेश, विनिर्माण विस्तार एवं औपचारिक रोजगार सृजन में तेजी

चरण 4
चरण 4: राजकोषीय घाटे में कमी (4.3% बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27) के साथ वित्त वर्ष 2026–27 में 6.8%–7.2% वास्तविक जीडीपी वृद्धि की प्राप्ति]`

2.4 तुलनात्मक सारणी: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के प्रमुख वृहद-आर्थिक संकेतक एवं संरचनात्मक रुझान

वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार	नवीनतम स्थिति (2026 संकलन)	मुख्य आर्थिक निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27)	वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव	**6.8% से 7.2% (वित्त वर्ष 2026–27)**	भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में कायम	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26
केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी)	महामारी-पूर्व औसत: **2.7% (जीडीपी का)**	**4.0% (जीडीपी का — वित्त वर्ष 2026 संकलन–25)**	बुनियादी ढाँचा परिसंपत्ति सृजन हेतु केंद्र के कैपेक्स और पूँजीगत अनुदानों में ऐतिहासिक उछाल	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26
राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी)	राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता	**2.4% (जीडीपी का)**	अनुसूचित जाति (50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण) ने राज्यों को उच्च कैपेक्स बनाए रखने हेतु प्रेरित किया	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26
संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती	वित्त वर्ष 2020–21 में **9.2%** तथा वित्त वर्ष 2021–22 में **6.7%**	**4.8% (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) \ 4.4% (संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2025–26) \ 4.3% (बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27)**	5 वर्षों में राजकोषीय घाटे को आधे से अधिक घटाकर संप्रभु साख को सुदृढ़ किया गया	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26
उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान	कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क	सीमा शुल्क युक्तिकरण द्वारा सुधार	घरेलू विनिर्माण इकाइयों की कार्यशील पूँजी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26

क्या आप जानते हैं?: भारत का **प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950–51** में केंद्रीय बजट के एक हिस्से के रूप में ही प्रस्तुत किया गया था; वर्ष **1964 से** आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में रखने की परंपरा शुरू हुई (आर्थिक सर्वेक्षण पोर्टल)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: 'आर्थिक सर्वेक्षण' को प्रस्तुत करने का कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है (यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाने वाला एक कार्यकारी दस्तावेज है), जबकि **'केंद्रीय बजट' (वार्षिक वित्तीय विवरण)** को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना **अनुच्छेद 112** के अंतर्गत राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष संवैधानिक दायित्व है (भारतीय संविधान)।

★ **स्मरण सूत्र:** आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के चार स्वर्णिम आँकड़े — **"वित्त वर्ष 2026–27 की जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2%, केंद्र का प्रभावी कैपेक्स 2.7% से बढ़कर 4.0%, राज्यों का कैपेक्स 2.4%, और वित्त वर्ष 2020–21 के 9.2% से घटकर आधे से भी कम (4.4% संशोधित अनुमान / 4.3% बजट अनुमान)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 3: केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार — अंश पुनर्खरीद, न्यूनतम वैकल्पिक कर, सीमा शुल्क युक्तिकरण एवं 16वाँ वित्त आयोग हस्तांतरण सूत्र

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 3: केंद्रीय बजट 2026–27 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार — अंश पुनर्खरीद, न्यूनतम वैकल्पिक कर, सीमा शुल्क युक्तिकरण एवं 16वाँ वित्त आयोग हस्तांतरण सूत्र

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
प्रत्यक्ष कर सुधार (कर): शेयर बायबैक कराधान, न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं विवाद समाधान	**अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सुधार: 17 कैंसर दवाओं पर छूट एवं कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली)**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बजट 2026–27 के कर सुधार एवं 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र**

3.1 प्रत्यक्ष कर सुधार (कर): शेयर बायबैक कराधान, न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं विवाद समाधान

• **शेयर बायबैक (अंश पुनर्खरीद) पर पूँजीगत लाभ (पूँजीगत लाभ) के रूप में कराधान:** केंद्रीय बजट 2026–27 में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए **शेयरों की पुनर्खरीद (अंश पुनर्खरीद)** से होने वाली आय पर **'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ)** के रूप में कर लगाने का प्रावधान किया गया है (इससे पहले 2024 से इसे लाभांश आय मानकर स्लैब दर पर कर लगाया गया था)। हालांकि, कर मध्यस्थता (कर) को रोकने और कॉर्पोरेट सुशासन सुनिश्चित करने के लिए **प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) को एक अतिरिक्त बायबैक कर (कर)** का भुगतान करना होगा (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

• **न्यूनतम वैकल्पिक कर (कर — न्यूनतम वैकल्पिक कर) सुधार एवं 1/4 क्रेडिट सेट-ऑफ:**

1. **मैट (न्यूनतम वैकल्पिक कर) को अंतिम कर (कर) बनाने का प्रस्ताव:** कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) को **अंतिम कर (कर)** बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

2. **नई कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट का 1/4 भाग समायोजन:** जिन कंपनियों के पास संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट उपलब्ध है, उन्हें नई कर व्यवस्था (कर) में अपनी कर देयता के **एक-चौथाई हिस्से तक उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट का उपयोग कर सेट-ऑफ (समायोजन)** करने की अनुमति दी गई है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

• **ईमानदार करदाताओं के लिए विवाद समापन योजना एवं एंजेल टैक्स की समाप्ति:**

1. **दंड के स्थान पर अतिरिक्त राशि देकर विवाद निपटान:** बजट 2026–27 में यह प्रावधान किया गया है कि जो ईमानदार करदाता अपने लंबित कर विवादों को सुलझाना चाहते हैं, वे **पेनल्टी (जुर्माने) के स्थान पर एक निर्धारित अतिरिक्त राशि** का भुगतान करके अपने मामलों को हमेशा के लिए बंद कर सकेंगे (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

2. **एंजेल टैक्स (कर — धारा 56(सात-ख)) की समाप्ति:** भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया गया है तथा विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर को 40% से घटाकर **35%** किया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

3.2 अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सुधार: 17 कैंसर दवाओं पर छूट एवं कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली)

• **कैंसर रोगियों के लिए 17 जीवनरक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (मूल सीमा शुल्क) से पूर्ण छूट:** स्वास्थ्य सेवा को सस्ता और सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026–27 में **कैंसर रोगियों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं या औषधियों** पर मूल सीमा शुल्क (— मूल सीमा शुल्क) को पूरी तरह **मुक्त** कर दिया गया है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

• **कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल डिजिटल विंडो एवं 'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम' (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली):**

1. **कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली — 2 वर्षों में रोलआउट):** अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को कागज-रहित, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आगामी **2 वर्षों में 'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम' (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली)** लागू करने की घोषणा की गई है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

2. **कार्गो क्लीयरेंस अनुमोदन के लिए एकल डिजिटल विंडो:** बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर माल की निकासी से संबंधित सभी विभिन्न नियामक एजेंसियों की मंजूरियों के लिए एक **एकल और परस्पर संबद्ध डिजिटल विंडो** स्थापित की जाएगी (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

• **कीमती धातुओं एवं महत्वपूर्ण खनिजों (महत्वपूर्ण खनिजों) पर शुल्क युक्तिकरण:** घरेलू मूल्य वर्धन और रत्न व आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सोने और चाँदी पर सीमा शुल्क घटाकर **6%** और प्लैटिनम पर **6.4%** किया गया है, तथा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे **25 महत्वपूर्ण खनिजों (महत्वपूर्ण खनिजों)** को मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क) से पूर्ण छूट दी गई है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

3.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बजट 2026–27 के कर सुधार एवं 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर युक्तिकरण — शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन्स टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट का 1/4 सेट-ऑफ एवं 17 कैंसर दवाओं पर मूल सीमा शुल्क छूट

चरण 2
चरण 2: 2 वर्षों में 'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम' (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल डिजिटल विंडो से व्यापार सुगमता

चरण 3
चरण 3: ₹28.67 लाख करोड़ के केंद्रीय शुद्ध कर राजस्व एवं ₹17.07 लाख करोड़ के अप्रत्यक्ष कर संग्रह का सुदृढ़ीकरण

चरण 4
चरण 4: 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 41% ऊर्ध्वाधर कर हिस्सेदारी एवं वित्त वर्ष 2026–27 में ₹1.4 लाख करोड़ के स्थानीय निकाय व आपदा अनुदान का हस्तांतरण]`

3.4 तुलनात्मक सारणी: केंद्रीय बजट (2026 संकलन) के प्रमुख कर और राजकोषीय सुधार प्रावधान

कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर	नवीनतम बजट प्रावधान (2026 संकलन)	लक्षित लाभार्थी एवं आर्थिक प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर)	घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान	सभी शेयरधारकों हेतु **'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ)** के रूप में कराधान; **प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) पर अतिरिक्त बायबैक कर**	खुदरा निवेशकों को पूँजीगत लागत कटौती का लाभ एवं प्रवर्तकों द्वारा कर बचाव पर रोक	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु
न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ	नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध	**न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर (कर)** बनाने का प्रस्ताव; नई कर व्यवस्था में **कर देयता के 1/4 तक न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट सेट-ऑफ** की अनुमति	विनिर्माण और बुनियादी ढाँचा कंपनियों को नई कर व्यवस्था अपनाने हेतु बड़ा प्रोत्साहन	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु
कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क)	3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार	कैंसर रोगियों के लिए **17 जीवनरक्षक दवाओं/ औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट**	कैंसर उपचार की लागत में भारी कमी और मरीजों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु
कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो	अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया	**2 वर्षों में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली का रोलआउट** एवं कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो	बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय में कमी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु
16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान	15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी	**41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी यथावत स्वीकार**; वित्त वर्ष 2026–27 हेतु राज्यों को **₹1.4 लाख करोड़** का वित्त आयोग अनुदान	ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) और आपदा प्रबंधन कोषों का सुदृढ़ीकरण	केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु
स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर	अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर	**एंजेल टैक्स (धारा 56(सात-ख)) पूर्णतः समाप्त**; विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटकर **35%**	भारतीय स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को प्रोत्साहन	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: न्यूनतम वैकल्पिक कर (कर — न्यूनतम वैकल्पिक कर, आयकर अधिनियम की धारा 115) की शुरुआत उन 'जीरो-टैक्स कंपनियों' (-कर) को कर के दायरे में लाने के लिए की गई थी जो कंपनी अधिनियम के तहत भारी किताबी लाभ कमाती थीं और लाभांश बाँटती थीं, किंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को शून्य दिखा देती थीं; गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं (जैसे) पर इसी के समतुल्य **'वैकल्पिक न्यूनतम कर' (— धारा 115)** लागू होता है (आईयूसी अकादमी)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: शेयर बायबैक कराधान में हुए क्रमिक बदलावों पर विशेष ध्यान दें: वर्ष 2026 संकलन से पहले कंपनी पर सेक्शन 115 के तहत 20% (+ सरचार्ज) बायबैक टैक्स लगता था; 2026 संकलन से इसे शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय माना गया; और अब **केंद्रीय बजट 2026–27** में इसे पुनः तर्कसंगत बनाते हुए **सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए 'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ)** के रूप में कर योग्य बनाया गया है, जबकि प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) पर अतिरिक्त बायबैक टैक्स लगाया गया है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

★ **स्मरण सूत्र:** बजट 2026–27 के कर और सीमा शुल्क सुधारों का सूत्र — **"बायबैक बना कैपिटल गेन्स (प्रमोटर पर अतिरिक्त कर), न्यूनतम वैकल्पिक कर बना फाइनल टैक्स (नई रिजीम में 1/4 क्रेडिट सेट-ऑफ), 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो, और 2 साल में लागू होगा कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 4: भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति 2026 — गवर्नर संजय मल्होत्रा के नीतिगत निर्णय, 5.50% रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात कटौती एवं तरलता प्रबंधन

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति 2026 — गवर्नर संजय मल्होत्रा के नीतिगत निर्णय, 5.50% रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात कटौती एवं तरलता प्रबंधन

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति) एवं 2025–2026 के प्रमुख नीतिगत निर्णय	**तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा), एसडीएफ (स्थायी जमा सुविधा), वीआरआरआर (परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो) एवं एचटीएम (परिपक्वता तक धारित) पोर्टफोलियो नियम**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आरबीआई का तरलता प्रबंधन एवं मौद्रिक नीति संचरण तंत्र (2026 संकलन)**

4.1 आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति) एवं 2025–2026 के प्रमुख नीतिगत निर्णय

• **मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति — धारा 45यख) की वैधानिक संरचना एवं मुद्रास्फीति लक्ष्य:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की **धारा 45यख** (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित, उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर) के अंतर्गत गठित **6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)** में 3 सदस्य आरबीआई के आंतरिक होते हैं — **आरबीआई गवर्नर (पदेन अध्यक्ष — संजय मल्होत्रा)**, मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी — तथा 3 बाह्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा **4 वर्ष के कार्यकाल** के लिए नियुक्त किए जाते हैं (जो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते)। लचीली मुद्रास्फीति लक्षीकरण रूपरेखा के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (— द्वारा जारी) पर आधारित मुद्रास्फीति का वैधानिक लक्ष्य **4% ± 2% (अर्थात् 2% से 6% का सहनशीलता बैंड)** निर्धारित है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मौद्रिक नीति वक्तव्य एवं सीआरआर (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की चरणबद्ध कटौती:**

1. **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की कटौती:** आरबीआई गवर्नर **संजय मल्होत्रा** द्वारा 6 जून 2025 को दिए गए मौद्रिक नीति वक्तव्य और जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता का संचार करने और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए सभी बैंकों के **नकद आरक्षित अनुपात (— सीआरआर) में चरणबद्ध रूप से 100 आधार अंकों (100 / 1 प्रतिशत)** की कटौती की घोषणा की गई (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन)।

2. **अक्टूबर 2026 मौद्रिक नीति एवं तरलता समायोजन सुविधा दरें (सीमांत स्थायी सुविधा एवं बैंक दर 5.75%):** आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2026 (07 अक्टूबर 2026) में जारी मौद्रिक नीति प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्रों (आरबीआई/2026-2027/282 एवं 283) के अनुसार, तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा) के अंतर्गत नीतिगत दरों में समायोजन के साथ **सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत** पर निर्धारित रही तथा अगस्त नीति के बाद से भारित औसत कॉल दर (भारित औसत कॉल दर) औसतन नीतिगत रेपो दर से 14 आधार अंक नीचे रही (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

4.2 तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा), एसडीएफ (स्थायी जमा सुविधा), वीआरआरआर (परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो) एवं एचटीएम (परिपक्वता तक धारित) पोर्टफोलियो नियम

• **तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा) के उपकरण — रेपो, एसडीएफ और एमएसएफ:**

1. **रेपो दर:** वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा (तरलता समायोजन सुविधा) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक (ओवरनाइट) ऋण प्रदान करता है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

2. **स्थायी जमा सुविधा (— स्थायी जमा सुविधा):** अप्रैल 2022 में आरबीआई अधिनियम की धारा 17 के तहत शुरू किया गया यह उपकरण तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर के **फ्लोर (निचली सीमा — सामान्यतः रेपो दर से 25 आधार अंक कम)** के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत आरबीआई **बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के संपार्श्विक** के बैंकों से अतिरिक्त तरलता अवशोषित करता है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

3. **सीमांत स्थायी सुविधा (— सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर:** यह तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की **सीलिंग (ऊपरी सीमा — सामान्यतः रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक, अक्टूबर 2026 में 5.75%)** है, जिसके तहत अनुसूचित बैंक अंतर-बैंक तरलता सूखने की आपात स्थिति में अपने **सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कोष में से (2% तक की सीमा में)** सरकारी प्रतिभूतियाँ रखकर आरबीआई से ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज बैंक दर से जुड़ा होता है (प्रथम दिन बैंक दर + 3% और अगले दिन से बैंक दर + 5%) (**आरबीआई परिपत्र सूची — नवंबर 2026**)।

4. **सप्ताहांत एवं अवकाश पर स्थायी जमा सुविधा व सीमांत स्थायी सुविधा उत्क्रमण तथा परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी:** बैंकों द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन के लिए आरबीआई ने सप्ताहांत और छुट्टियों के दिनों में भी स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दोनों के तहत तरलता सुविधाओं के उत्क्रमण की अनुमति दी है, तथा बैंकिंग प्रणाली की अधिशेष तरलता को प्रबंधित करने के लिए नवंबर 2026 में 2-दिवसीय **परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (— परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो)** नीलामियों का संचालन किया है (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — 16 नवंबर 2026**)।

• **एसएलआर (एसएलआर) और 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (परिपक्वता तक धारित) सीमा की चरणबद्ध बहाली:** आरबीआई ने महामारी के दौरान बैंकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के बेहतर प्रबंधन हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की **'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (— परिपक्वता तक धारित)** सीमा को शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ) के 22% से बढ़ाकर **23%** किया था, जिसे 2026 संकलन को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से घटाकर पुनः **19.5 प्रतिशत** पर बहाल करने की व्यवस्था लागू की गई है (**आरबीआई प्रकाशन**)।

4.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: आरबीआई का तरलता प्रबंधन एवं मौद्रिक नीति संचरण तंत्र (2026 संकलन)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा मुद्रास्फीति (4% ± 2% लक्ष्य) एवं वृद्धि की द्वि-मासिक समीक्षा

चरण 2
चरण 2: बैंकों में टिकाऊ तरलता बढ़ाने हेतु सीआरआर में 100 आधार अंकों की चरणबद्ध कटौती एवं तरलता समायोजन सुविधा दरों (सीमांत स्थायी सुविधा/ 5.75%) का समायोजन

चरण 3
चरण 3: अल्पकालिक अधिशेष तरलता के अवशोषण हेतु परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी एवं बिना संपार्श्विक वाले स्थायी जमा सुविधा (सप्ताहांत उत्क्रमण सहित) का संचालन

चरण 4
चरण 4: भारित औसत कॉल दर (भारित औसत कॉल दर) का रेपो दर के अनुरूप संरेखण एवं अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को सस्ती ऋण उपलब्धता]`

4.4 तुलनात्मक सारणी: आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण, आरक्षित अनुपात एवं नियामक निर्देश (2026 संकलन)

मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	वैधानिक आधार / धारा	प्रमुख विशेषता एवं कार्यप्रणाली	नवीनतम स्थिति / दंडात्मक प्रावधान (2026 संकलन)	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 45यख**	6 सदस्य (3 आरबीआई आंतरिक + 3 सरकार द्वारा नामित बाह्य सदस्य); गवर्नर के पास निर्णायक मत	लगातार 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति 2%–6% बैंड से बाहर रहने पर केंद्र सरकार को जवाबदेही रिपोर्ट (धारा 45यढ)	**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 42**	प्रत्येक बैंक को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित प्रतिशत केवल **नकद रूप में आरबीआई के पास** रखना होता है (बैंकों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता)	जून 2025 की घोषणा के तहत सीआरआर में **100 आधार अंकों (100 आधार अंक) की चरणबद्ध कटौती**	**आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन**
सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की **धारा 24**	बैंकों को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित भाग **स्वयं के पास** नकद, स्वर्ण या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है	परिपक्वता तक धारित सीमा का 23% से **19.5%** पर चरणबद्ध पुनर्स्थापन	**आरबीआई प्रकाशन**
स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 17**	तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की निचली सीमा; **संपार्श्विक-मुक्त** तरलता अवशोषण उपकरण	रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे; सप्ताहांत व अवकाश पर भी उत्क्रमण की सुविधा	**आरबीआई प्रकाशन**

मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	वैधानिक आधार / धारा	प्रमुख विशेषता एवं कार्यप्रणाली	नवीनतम स्थिति / दंडात्मक प्रावधान (2026 संकलन)	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर	आरबीआई अधिनियम, 1934 की **धारा 49 (बैंक दर)**	तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की ऊपरी सीमा; एसएलआर कोटे में से ओवरनाइट आपात उधार	अक्टूबर 2026 के अनुसार **सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.75%**; सीआरआर/एसएलआर कमी पर दंडात्मक ब्याज बैंक दर से संबद्ध	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026
जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट	फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन	शिपिंग पोत के आयात हेतु बिना बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के अग्रिम विप्रेषण	जून 2025 के परिपत्र द्वारा **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 50 मिलियन)** तक बिना बैंक गारंटी अग्रिम भुगतान की छूट	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन

क्या आप जानते हैं?: वर्ष 2006 के संशोधन से पहले आरबीआई अधिनियम के तहत नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की न्यूनतम सीमा 3% और अधिकतम सीमा 15% थी, तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की न्यूनतम सीमा 25% थी; किंतु **आरबीआई (संशोधन) अधिनियम, 2006** द्वारा सीआरआर की न्यूनतम व अधिकतम दोनों सीमाएँ समाप्त कर दी गईं और **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2007** द्वारा एसएलआर की 25% की निचली सीमा को समाप्त कर दिया गया (जबकि एसएलआर की अधिकतम सीमा **40%** आज भी कानून में निर्धारित है) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा) और **रिवर्स रेपो दर** के बीच सबसे बड़ा तकनीकी अंतर यह है कि रिवर्स रेपो के तहत जब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो आरबीआई को बदले में बैंकों को **सरकारी प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक के रूप में देनी पड़ती हैं**, जबकि **स्थायी जमा सुविधा (अप्रैल 2022 से तरलता समायोजन सुविधा का नया फ्लोर)** में आरबीआई को कोई संपार्श्विक देने की आवश्यकता नहीं होती; इसके अतिरिक्त, **स्थायी जमा सुविधा के तहत जमा राशि एसएलआर (एसएलआर) के लिए पात्र नहीं होती**, किंतु नकदी कवरेज अनुपात के तहत उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों में गिनी जाती है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

★ **स्मरण सूत्र:** आरबीआई के तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर का क्रम (नीचे से ऊपर) याद रखने का सूत्र — **"सबसे नीचे बिना गिरवी वाला स्थायी जमा सुविधा (रेपो - 0.25%), बीच में मुख्य नीतिगत रेपो दर, और सबसे ऊपर आपातकालीन सीमांत स्थायी सुविधा व बैंक दर (रेपो + 0.25% = अक्टूबर 2026 में 5.75%)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 5: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग मानदंड, बेसल मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं आरबीआई डिजिटल मंच

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सुधार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग मानदंड, बेसल मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं आरबीआई डिजिटल मंच

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए इंटरनेट बैंकिंग पात्रता मानदंडों में संशोधन एवं बैंकिंग सुदृढ़ता

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निदेश 2025, बेसल-मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं प्रमुख आरबीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) को इंटरनेट बैंकिंग अनुमति मिलने का संशोधित नियामक चक्र

5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए इंटरनेट बैंकिंग पात्रता मानदंडों में संशोधन एवं बैंकिंग सुदृढ़ता

• **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के संशोधित वित्तीय मानदंड:** डिजिटल वित्तीय समावेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई तक पहुँचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों — नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित; पूँजी संरचना: **केंद्र सरकार 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15%**) के लिए इंटरनेट बैंकिंग (लेन-देन सुविधा सहित) शुरू करने के पात्रता मानदंडों को उदार बनाया है:

1. **न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी पर्याप्तता अनुपात):** पहले न्यूनतम 10 प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात अनिवार्य था, जिसे संशोधित कर **न्यूनतम निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अनुपात (वर्तमान में 9 प्रतिशत)** कर दिया गया है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

2. **न्यूनतम निवल मालियत:** पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को न्यूनतम निवल मालियत की आवश्यकता को **₹100 करोड़ या अधिक से घटाकर ₹50 करोड़ या अधिक** कर दिया गया है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

3. **आस्ति गुणवत्ता (— एनपीए मानदंड):** पहले सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (सकल एनपीए) 7% से कम और निवल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (शुद्ध एनपीए) 3% से अनधिक होनी आवश्यक थीं; संशोधित मानदंड के तहत केवल यह शर्त रखी गई है कि पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को **शुद्ध एनपीए अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक नहीं** होना चाहिए (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

4. **लाभप्रदता:** पहले ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ और पिछले चार में से कम-से-कम तीन वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ आवश्यक था; अब केवल **ठीक पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ** और कोई संचित हानि न होने की शर्त रखी गई है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

5.2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निदेश 2025, बेसल- मानक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण एवं प्रमुख आरबीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म

• **भारतीय रिजर्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 (आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच , 2025):** आरबीआई ने 16 जून 2025 को 2018 के ढाँचे की समीक्षा के बाद **'भारतीय रिजर्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025'** जारी किए हैं। ये निदेश सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार उपकरणों, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव में लेन-देन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालकों के पंजीकरण, जोखिम प्रबंधन, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग नियंत्रण और बाजार पारदर्शिता को विनियमित करते हैं (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• **एनबीएफसी पंजीकरण निगरानी एवं पैमाना-आधारित विनियमन:** आरबीआई के पैमाना-आधारित विनियमन ढाँचे में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके आकार, गतिविधि और प्रणालीगत जोखिम के आधार पर **चार स्तरों** में वर्गीकृत किया गया है: **आधार स्तर, मध्यम स्तर, ऊपरी स्तर** और **शीर्ष स्तर**। नवंबर 2026 में आरबीआई ने कड़े विनियामक अनुपालन के तहत 49 के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए तथा 13 और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित किए (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — 16 नवंबर 2026)।

• **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (— प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) के मुख्य लक्ष्य:**

1. **घरेलू वाणिज्यिक बैंक एवं विदेशी बैंक (20 या अधिक शाखाओं वाले):** समायोजित निवल बैंक ऋण का कुल **40 प्रतिशत** (जिसमें कृषि हेतु **18%** — लघु एवं सीमांत किसानों हेतु 10%; सूक्ष्म इकाइयों हेतु 7.5%; और कमजोर वर्गों हेतु **12%** शामिल है) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

2. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) एवं लघु वित्त बैंक (— लघु वित्त बैंकों):** अपने का कुल **75 प्रतिशत** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अनिवार्य है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

3. **प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक (- — शहरी सहकारी बैंकों):** अपने का **60 प्रतिशत** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **आरबीआई के प्रमुख नागरिक एवं नियामक डिजिटल पोर्टल (उद्गम, प्रवाह, दक्ष एवं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब):**

1. **उद्गम पोर्टल (उद्गम — :):** नागरिकों को विभिन्न बैंकों में पड़े अपने **लावारिस जमा (— 10 वर्ष या अधिक से निष्क्रिय खाते, जो फंड में स्थानांतरित हो जाते हैं)** को एक ही स्थान पर खोजने और दावा करने की सुविधा देता है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

2. **प्रवाह पोर्टल (प्रवाह — ,):** किसी भी व्यक्ति या विनियमित इकाई द्वारा आरबीआई से विभिन्न विनियामक अनुमोदन, लाइसेंस और अनुमतियाँ ऑनलाइन प्राप्त करने का केंद्रीकृत पोर्टल (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

3. **दक्ष पोर्टल (दक्ष):** बैंकों और की अनुपालन संस्कृति और साइबर घटना रिपोर्टिंग की निगरानी के लिए आरबीआई की उन्नत पर्यवेक्षी प्रणाली (**सुपरटेक**) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

4. **म्यूलहंटर.एआई (म्यूलहंटर-एआई):** रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआई, बेंगलुरु) द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/) मॉडल जो बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रयुक्त होने वाले **'म्यूल बैंक खातों'** की त्वरित पहचान और रोकथाम करता है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

5.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) को इंटरनेट बैंकिंग अनुमति मिलने का संशोधित नियामक चक्र

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को न्यूनतम निवल मालियत ₹50 करोड़ या अधिक एवं न्यूनतम निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9% की पूर्ति

चरण 2
चरण 2: आस्ति गुणवत्ता में सुधार — निवल एनपीए (शुद्ध एनपीए) अनुपात अधिकतम 5% के भीतर एवं पिछले लगातार 2 वर्षों में शुद्ध लाभ

चरण 3
चरण 3: कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, साइबर सुरक्षा ऑडिट (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं संचित हानि शून्य होने के प्रमाण का आरबीआई को प्रस्तुतीकरण

चरण 4
चरण 4: आरबीआई द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पूर्ण लेन-देन आधारित इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने की मंजूरी]`

5.4 तुलनात्मक सारणी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) इंटरनेट बैंकिंग मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य एवं प्रमुख आरबीआई पोर्टल

नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य	नवीनतम संशोधित मानदंड / कार्यप्रणाली (2026 संकलन)	मुख्य प्रभाव एवं परीक्षा-उन्मुख तथ्य	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत	₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को)	**₹50 करोड़ या अधिक** (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को)	अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ देने में सक्षम बनाया गया	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात एवं शुद्ध एनपीए सीमा	पूँजी पर्याप्तता अनुपात \ 10%; सकल एनपीए < 7% व शुद्ध एनपीए \ 3%	**न्यूनतम निर्धारित पूँजी पर्याप्तता अनुपात (वर्तमान में 9%)** तथा **शुद्ध एनपीए अनुपात अधिकतम 5% (\ 5%)**	सकल एनपीए की दोहरी शर्त हटाकर केवल शुद्ध एनपीए \ 5% का व्यावहारिक मानदंड रखा गया	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त	पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ	**ठीक पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ**	ग्रामीण बैंकों के लिए पात्रता प्रक्रिया का सरलीकरण	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य	वाणिज्यिक बैंक: 40% \	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/लघु वित्त बैंक: 75% \	पेमेंट्स बैंक: 0% (ऋण नहीं देते)	कृषि: **18%** (लघु-सीमांत किसान **10%**), सूक्ष्म इकाइयाँ: **7.5%**, कमजोर वर्ग: **12%**	शहरी सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य **60%** निर्धारित	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष)	पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ	**उद्गम:** लावारिस जमा खोज पोर्टल \	**प्रवाह:** विनियामक लाइसेंस पोर्टल \	**दक्ष:** आरबीआई सुपरटेक पोर्टल	ग्राहकों और विनियमित संस्थाओं के लिए पारदर्शी सिंगल-विंडो डिजिटल समाधान	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ)	टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती	अवधि दिसंबर 2025 तक विस्तारित; **पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों** को भी पीआईडीएफ में शामिल किया गया	जमीनी स्तर पर कारीगरों और छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान उपकरणों का प्रसार	आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन

क्या आप जानते हैं?: बेसल- मानकों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी पर्याप्तता अनुपात /) 8% निर्धारित है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात **9 प्रतिशत** (तथा इसके ऊपर **2.5 प्रतिशत का पूँजी संरक्षण बफर** — , अर्थात् कुल **11.5 प्रतिशत**) निर्धारित कर रखा है। भारत में वर्तमान में तीन बैंकों — **भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक (एचडीएफसी बैंक) और आईसीआईसीआई बैंक (केंद्रीय सूचना आयोग)** — को **'घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक' (डी-एसआईबी — विफल होने के लिए अत्यंत विशाल)** की श्रेणी में रखा गया है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: भुगतान बैंकों (— नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्थापित) और **लघु वित्त बैंकों (— उषा थोराट समिति की सिफारिश पर स्थापित)** में यह मूलभूत अंतर याद रखें: भुगतान बैंक प्रति ग्राहक **अधिकतम ₹2 लाख तक की माँग जमा (— बचत व चालू खाता)** स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वे **न तो सावधि जमा स्वीकार कर सकते हैं और न ही कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं**; जबकि लघु वित्त बैंक सभी प्रकार की जमाएँ स्वीकार कर सकते हैं और ऋण भी दे सकते हैं (जिनका 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में होना अनिवार्य है) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

★ **स्मरण सूत्र:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के संशोधित इंटरनेट बैंकिंग मानदंडों का सूत्र — **"50 करोड़ की नेटवर्थ, 9% का सीआरएआर (पूँजी पर्याप्तता अनुपात), 5% से कम नेट एनपीए (शुद्ध एनपीए) और पिछले 2 साल का लगातार मुनाफा — आरआरबी को दिलाए इंटरनेट बैंकिंग का तोहफा!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 6: डिजिटल भुगतान क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के 2026 परिपत्र, यूपीआई लाइट, यूपीआई सर्कल, व्यापार सक्षम एवं डिजिटल रुपया

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 6: डिजिटल भुगतान क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के 2026 परिपत्र, यूपीआई लाइट, यूपीआई सर्कल, व्यापार सक्षम एवं डिजिटल रुपया

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और यूपीआई (यूपीआई) पारिस्थितिकी तंत्र के नवीनतम नवाचार (2026 संकलन)	उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई विस्तार एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी / -)	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: एनपीसीआई के आधुनिक यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र (यूपीआई , यूपीआई सर्कल व यूपीआई) की कार्यप्रणाली

6.1 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और यूपीआई (यूपीआई) पारिस्थितिकी तंत्र के नवीनतम नवाचार (2026 संकलन)

• **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की संस्थागत पृष्ठभूमि: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ की एक पहल के रूप में वर्ष **2008 में** स्थापित एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन हेतु एक अंब्रेला संगठन है (जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत 'गैर-लाभकारी कंपनी' के रूप में निगमित किया गया है)। इसके प्रमुख उत्पादों में **यूपीआई (2016 में लॉन्च), कार्ड, , (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस), , , अनुसूचित जनजाति और भारत बिलपे** शामिल हैं (एनपीसीआई आधिकारिक पोर्टल)।

• **यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट) — ₹1,000 से कम के पिन-रहित त्वरित लेन-देन:**

1. **प्रति लेन-देन सीमा एवं कार्यप्रणाली:** एनपीसीआई के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, **यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)** एक 'ऑन-डिवाइस वॉलेट' समाधान है जिसे **₹1,000 से कम (₹1,000)** के कम मूल्य के खुदरा लेन-देन को **बिना यूपीआई पिन** के तीव्र गति से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वास्तविक समय में बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम पर भार कम होता है (एनपीसीआई — यूपीआई लाइट)।

2. **कुल वॉलेट सीमा एवं ऑटो-टॉपअप:** आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की कुल बैलेंस सीमा को ₹2,000 से बढ़ाकर **₹5,000** किया है तथा इसमें ई-मैंडेट के माध्यम से **'ऑटो-रिप्लेनिशमेंट' (-- — बैलेंस निर्धारित सीमा से नीचे जाने पर बैंक खाते से स्वतः राशि लोड होना)** की सुविधा भी जोड़ दी है। मोबाइल डिवाइस बदलने से पहले उपयोगकर्ता को पुराने फोन से खाता डिसेबल करना होता है ताकि शेष राशि स्वतः मूल बैंक खाते में वापस चली जाए (एनपीसीआई — यूपीआई लाइट)।

• **वित्त वर्ष 2026–27 के नवीनतम एनपीसीआई परिपत्र एवं यूपीआई नवाचार (यूपीआई सर्कल, यूपीआई, & ,):**

1. **यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल — प्रत्यायोजित भुगतान):** यह सुविधा एक **प्राथमिक यूपीआई उपयोगकर्ता** को अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों (**द्वितीयक उपयोगकर्ताओं** / — भले ही उनका अपना बैंक खाता यूपीआई से लिंक न हो) को अपने बैंक खाते से निर्धारित सीमा के भीतर भुगतान करने का अधिकार देने (करने) की अनुमति देती है। इसमें दो विकल्प हैं — **'आंशिक प्रत्यायोजन' (: जहाँ प्रत्येक भुगतान पर प्राथमिक उपयोगकर्ता अपना पिन डालकर मंजूरी देता है)** और **'पूर्ण प्रत्यायोजन' (: जहाँ प्राथमिक उपयोगकर्ता ₹15,000 तक की मासिक सीमा और ₹5,000 तक की प्रति लेन-देन सीमा तय कर देता है)** (एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र)।

2. **यूपीआई व्यापार सक्षम योजना (यूपीआई — परिचालन परिपत्र 242, वित्त वर्ष 26–27):** छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) के बीच यूपीआई भुगतान की स्वीकार्यता को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए एनपीसीआई द्वारा वित्त वर्ष 2026–27 में **'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना'** जारी की गई है (एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र)।

3. **'माई-यूपीआई' — एआई-संचालित सहायता ('यूपीआई' / यूपीआई सहायता 2.0 — परिचालन परिपत्र 227, वित्त वर्ष 26–27):** यूपीआई भुगतानों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान और ग्राहक सहायता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से लैस **'माई-यूपीआई' (यूपीआई सहायता 2.0)** प्रणाली लागू की गई है, तथा 2 विवादों के मानकीकरण हेतु नए परिपत्र जारी किए गए हैं (एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र)।

4. **पीओएस पर यूपीआई टैप एंड पे (यूपीआई & पीओएस — परिचालन परिपत्र 186, वित्त वर्ष 26–27):** एनएफसी (एनएफसी —) तकनीक का उपयोग करते हुए प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर सीधे फोन टैप करके यूपीआई भुगतान करने की सुविधा का विस्तार किया गया है (एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र)।

6.2 उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई विस्तार एवं केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी / -)

• **यूपीआई की लेन-देन सीमाएँ:** सामान्य पीयर-टू-पीयर और मर्चेंट यूपीआई भुगतानों के लिए प्रति लेन-देन सीमा **₹1 लाख** है; किंतु पूँजी बाजार, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान व विदेशी यात्रा के लिए यह सीमा **₹2 लाख** है, और **अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजनाओं, आईपीओ आवेदनों तथा कर भुगतान (कर)** के लिए प्रति लेन-देन सीमा बढ़ाकर **₹5 लाख** कर दी गई है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **यूपीआई का वैश्विक विस्तार (एनपीसीआई —):** एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा के माध्यम से भारत का यूपीआई फ्रांस (एफिल टॉवर से यूरोप में शुरुआत), संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर (*** के साथ रियल-टाइम लिंकेज), भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरीशस सहित अनेक देशों में स्वीकार किया जा रहा है, तथा यूपीआई परिचालन परिपत्र संख्या 161* के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई संचालन की अनुमत देशों की सूची में नए देशों को जोड़ा गया है (एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र)।

• **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी — डिजिटल रुपया / ₹):** आरबीआई द्वारा जारी **ई-रुपया (ई-रुपया)** भौतिक करेंसी नोटों का ही संप्रभु डिजिटल रूप है जो आरबीआई की बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दर्ज होता है। इसके दो प्रकार हैं: **खुदरा डिजिटल रुपया (ई-रुपया खुदरा / सीबीडीसी):** आम नागरिकों और व्यापारियों के दैनिक लेन-देन हेतु (टोकन-आधारित, जिसे ऑफलाइन और प्रोग्रामेबल सब्सिडी वितरण हेतु भी सक्षम बनाया गया है); और **थोक डिजिटल रुपया (ई-रुपया थोक / सीबीडीसी):** अंतर-बैंक निपटान और सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार के त्वरित निपटान हेतु (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

6.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: एनपीसीआई के आधुनिक यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र (यूपीआई , यूपीआई सर्कल व यूपीआई) की कार्यप्रणाली

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: उपयोगकर्ता द्वारा बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड की यूपीआई लिंकिंग एवं ₹5,000 सीमा वाले ऑन-डिवाइस 'यूपीआई ' का ऑटो-टॉपअप सक्रियण

चरण 2
चरण 2: ₹1,000 से कम के खुदरा भुगतानों का बिना पिन एवं 'यूपीआई & पीओएस' (एनएफसी) के माध्यम से त्वरित निष्पादन

चरण 3
चरण 3: 'यूपीआई सर्कल' के तहत आश्रित परिवारजनों को पूर्ण प्रत्यायोजन (₹15,000/माह) या आंशिक प्रत्यायोजन से भुगतान अधिकार

चरण 4
चरण 4: किसी भी तकनीकी विवाद की स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित 'यूपीआई (यूपीआई 2.0)' एवं मानकीकृत 2 विवाद तंत्र द्वारा स्वतः निवारण]`

6.4 तुलनात्मक सारणी: एनपीसीआई के प्रमुख डिजिटल भुगतान उत्पाद, सीमाएँ एवं 2025–2026 के नवीनतम परिपत्र

डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	मुख्य तकनीकी विशेषता	प्रति लेन-देन / कुल सीमा	वित्त वर्ष 2025–27 के नवीनतम नवीनतम विवरण / परिपत्र	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)	ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान	प्रति लेन-देन: **₹1,000 से कम (₹1,000)** \	कुल वॉलेट सीमा: **₹5,000**	ई-मैंडेट आधारित ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा लागू; फोन बदलने पर पुराना डिसेबल करने से बैंक खाते में रिफंड	एनपीसीआई — यूपीआई लाइट
यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)	प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन	पूर्ण प्रत्यायोजन में: **₹15,000 मासिक** एवं **₹5,000 प्रति लेन-देन**	एक प्राथमिक उपयोगकर्ता अधिकतम 5 द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकता है	एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र	
यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)	बिना इंटरनेट वाले **फीचर फोन** के लिए यूपीआई भुगतान	प्रति लेन-देन सीमा: **₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000** की गई	4 तकनीकें: नंबर कॉल, फीचर फोन ऐप, मिस्ड कॉल और प्रॉक्सिमिटी साउंड-आधारित भुगतान	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	

डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	मुख्य तकनीकी विशेषता	प्रति लेन-देन / कुल सीमा	वित्त वर्ष 2025–27 के नवीनतम नवीनतम विवरण / परिपत्र	आधिकारिक सत्यापन स्रोत		
माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0)	एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान	247 स्वचालित शिकायत निवारण और रीयल-टाइम ट्रैकिंग	परिपत्र **यूपीआई परिचालन परिपत्र संख्या 227 (वित्त वर्ष 2026–27)** एवं 2 विवाद मानकीकरण	एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र		
यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे	छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान	छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) और संपर्क-रहित पीओएस भुगतानों पर केंद्रित	परिपत्र **यूपीआई परिचालन परिपत्र 242 (वित्त वर्ष 26–27 — व्यापार सक्षम)** एवं **परिचालन परिपत्र 186 (वित्त वर्ष 26–27 — & पीओएस)**	एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र		
मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ	2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर	सामान्य: **₹1 लाख** |	पूँजी बाजार/बीमा: **₹2 लाख** |	अस्पताल/शिक्षा/टैक्स/ आईपीओ: **₹5 लाख**	कर भुगतान (कर) और अस्पताल/शिक्षा शुल्क हेतु ₹5 लाख की उच्च सीमा	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

क्या आप जानते हैं?: एनपीसीआई द्वारा जारी **'भीम-यूपीआई ब्रांडिंग दिशानिर्देश' (-यूपीआई , जून 2026 में अद्यतन)** के अनुसार, सभी यूपीआई ऐप्स में उपयोगकर्ता की **यूपीआई का फॉन्ट आकार ऊँचाई में ऐप के लोगो के आकार के बराबर** और स्पष्ट रूप से पठनीय होना अनिवार्य है ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की दृश्य त्रुटि न हो (एनपीसीआई भीम-यूपीआई दिशानिर्देश — जून 2026)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: यूपीआई (यूपीआई) और **डिजिटल रुपया (सीबीडीसी / ई-रुपया)** के बीच के बुनियादी अंतर को कभी न भूलें: **यूपीआई एक भुगतान अंतरफलक** है जिसमें पैसा एक वाणिज्यिक बैंक खाते से दूसरे वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित होता है (अर्थात् यह संबंधित बैंक की देयता है); जबकि **डिजिटल रुपया (ई-रुपया) स्वयं एक वैध मुद्रा** है जो सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर देयता है और इसके लेन-देन के लिए उपयोगकर्ता के पास बैंक खाता होना भी अनिवार्य नहीं है (यह एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में नकद की तरह तुरंत अंतिम निपटान करता है) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

★ **स्मरण सूत्र:** यूपीआई के विशेष फीचर्स की राशि सीमाएँ याद रखने का सूत्र — **"यूपीआई में बिना पिन ₹1,000 से कम (वॉलेट ₹5,000); यूपीआई 123पे (फीचर फोन) में ₹10,000; यूपीआई सर्कल में ₹15,000 मासिक; सामान्य यूपीआई में ₹1 लाख; और अस्पताल-शिक्षा-टैक्स-आईपीओ में पूरे ₹5 लाख!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 7: वस्तु एवं सेवा कर वास्तुकला, 56वीं एवं 57वीं जीएसटी परिषद बैठक (अक्टूबर 2026) के निर्णय, अपीलीय न्यायाधिकरण एवं धारा 128क समाधान योजना

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 7: वस्तु एवं सेवा कर वास्तुकला, 56वीं एवं 57वीं जीएसटी परिषद बैठक (अक्टूबर 2026) के निर्णय, अपीलीय न्यायाधिकरण एवं धारा 128क समाधान योजना

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
जीएसटी संवैधानिक ढाँचा (101वाँ संशोधन) एवं जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क) की मतदान संरचना	**हालिया जीएसटी परिषद बैठकों (53वीं–55वीं) के प्रमुख निर्णय, धारा 128क माफी योजना एवं जीसैट (जीएसटी)**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: जीएसटी विवाद निवारण एवं अपीलीय पदानुक्रम (जीएसटी एवं नई मौद्रिक सीमाएँ)**

7.1 जीएसटी संवैधानिक ढाँचा (101वाँ संशोधन) एवं जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क) की मतदान संरचना

• **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 एवं केलकर समिति की पृष्ठभूमि:** विजय केलकर टास्क फोर्स और असीम दासगुप्ता समिति के कार्य के आधार पर पारित **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** द्वारा **1 जुलाई 2017** से भारत में 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के सिद्धांत पर **गंतव्य-आधारित मूल्य वर्धित कर (- कर)** के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया। इसके तीन मुख्य घटक हैं — **जीएसटी** (केंद्र द्वारा संग्रहीत), **जीएसटी/ जीएसटी** (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा संग्रहीत) और अंतर-राज्यीय व्यापार व आयात पर **जीएसटी** (अनुच्छेद 269क के तहत केंद्र द्वारा संग्रहीत और गंतव्य राज्य के साथ विभाजित) (भारतीय संविधान)।

• **अनुच्छेद 279क — जीएसटी परिषद (जीएसटी) की संरचना एवं भारित मतदान प्रणाली:**

1. **संरचना: केंद्रीय वित्त मंत्री** इसके पदेन **अध्यक्ष** होते हैं; केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री सदस्य होते हैं; तथा सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के वित्त/कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं (**भारतीय संविधान**)।

2. **गणपूर्ति एवं मतदान भार:** जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कुल सदस्यों के **आधे** की गणपूर्ति अनिवार्य है। परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के **कम-से-कम तीन-चौथाई (3/4 अर्थात् 75%) बहुमत** से लिया जाता है, जिसमें **केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3\{} = 33.33%)** और **सभी राज्यों के संयुक्त मतों का भार दो-तिहाई (2/3\{} = 66.67%)** होता है। इसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले और न ही राज्य अकेले कोई निर्णय पारित कर सकते हैं (**मोहित मिनरल्स बनाम भारत संघ, 2022** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए 'प्रेरक मूल्य' रखती हैं ताकि सहकारी संघवाद बना रहे) (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

7.2 हालिया जीएसटी परिषद बैठकों (53वीं–55वीं) के प्रमुख निर्णय, धारा 128क माफी योजना एवं जीसैट (जीएसटी)

• **फर्जी चालान रोकने हेतु अखिल भारतीय बायोमेसूत्र आधार प्रमाणीकरण:** जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों और मुखौटा पंजीकरणों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में जोखिम मापदंडों के आधार पर नए जीएसटी आवेदकों के लिए **बायोमेसूत्र-आधारित आधार प्रमाणीकरण** और भौतिक सत्यापन की प्रणाली लागू की गई है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **जीएसटी अधिनियम की नई धारा 128क — शुरुआती वर्षों के कर विवादों में ब्याज और जुर्माने की माफी:** जीएसटी के प्रारंभिक तीन वित्तीय वर्षों (**2017–18, 2018–19 और 2019–20**) के दौरान गैर-धोखाधड़ी (धारा 73) वाले मामलों में जारी किए गए मांग नोटिसों में, यदि करदाता निर्धारित तिथि तक मूल कर राशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो **नई धारा 128क** के अंतर्गत उस पर लगने वाले **ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ** करने की ऐतिहासिक राहत दी गई है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी — जीएसटी) का परिचालन एवं अपील सीमाएँ:**

1. **जीएसटी की संरचना:** प्रथम अपील अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने के लिए **नई दिल्ली में जीएसटी की प्रधान पीठ** और राज्यों में विभिन्न राज्य पीठों को क्रियाशील बनाया गया है (प्रत्येक पीठ में 2 न्यायिक सदस्य, 1 केंद्रीय तकनीकी सदस्य और 1 राज्य तकनीकी सदस्य होते हैं; न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया) (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

2. **विभाग द्वारा मुकदमेबाजी घटाने हेतु मौद्रिक सीमाएँ:** कर विवादों का बोझ कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने की न्यूनतम मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की हैं: **जीएसटी के समक्ष ₹20 लाख, उच्च न्यायालय के समक्ष ₹1 करोड़**, और **सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ₹2 करोड़** (अर्थात् इससे कम कर राशि के मामलों में विभाग सामान्यतः अपील दायर नहीं करेगा) (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

3. **अपील हेतु पूर्व-जमा (पूर्व-जमा) में भारी कटौती:** करदाताओं को राहत देते हुए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिकतम पूर्व-जमा राशि ₹25 करोड़ से घटाकर **₹20 करोड़** (जीएसटी व जीएसटी प्रत्येक) तथा जीएसटी के समक्ष पूर्व-जमा को 20% से घटाकर **10%** (अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ से घटाकर **₹20 करोड़** प्रत्येक) कर दिया गया है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की अनिवार्यता एवं कर दर युक्तिकरण:** 1 अप्रैल 2025 से बहु-राज्यीय कार्यालयों वाली कंपनियों के लिए सामान्य इनपुट सेवाओं के क्रेडिट वितरण हेतु **इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर** तंत्र को अनिवार्य बनाया गया है (जिसके अनुरूप एनपीसीआई ने भी अपने बैंक-ऑफिस सिस्टम में यूपीआई परिचालन परिपत्र-229 के तहत भारतीय मानक जीएसटी विकल्प जोड़ा है)। इसके अलावा, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों, बैटरी चालित वाहनों व छात्रावास आवास (₹20,000 प्रति माह तक और न्यूनतम 90 दिन रहने पर) को जीएसटी से छूट दी गई है तथा सभी प्रकार के दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर एकसमान **12% जीएसटी** निर्धारित किया गया है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

7.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: जीएसटी विवाद निवारण एवं अपीलीय पदानुक्रम (जीएसटी एवं नई मौद्रिक सीमाएँ)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का आदेश एवं धारा 128क के तहत वित्त वर्ष 2017–18–वित्त वर्ष20 के मामलों में मूल कर भुगतान पर ब्याज-जुर्माना माफी

चरण 2
चरण 2: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील (विवादित कर का 10% पूर्व-जमा, अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ जीएसटी + ₹20 करोड़ जीएसटी)

चरण 3
चरण 3: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी — प्रधान पीठ नई दिल्ली) में द्वितीय अपील (अतिरिक्त 10% पूर्व-जमा; विभागीय अपील सीमा ₹20 लाख)

चरण 4
चरण 4: विधि के सारवान प्रश्न पर उच्च न्यायालय (विभागीय सीमा ₹1 करोड़) एवं सर्वोच्च न्यायालय (विभागीय सीमा ₹2 करोड़) में अपील]`

7.4 तुलनात्मक सारणी: जीएसटी संवैधानिक प्रावधान, अपीलीय सीमाएँ एवं हालिया जीएसटी परिषद सुधार

जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र	संवैधानिक अनुच्छेद / वैधानिक धारा	प्रमुख नियम / संख्यात्मक मानदंड	करदाताओं एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत		
जीएसटी परिषद की मतदान संरचना	**अनुच्छेद 279क** (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)	गणपूर्ति: **50%** |	निर्णय बहुमत: **75%** |	मत भार: **केंद्र 1/3 + राज्य 2/3**	सहकारी संघवाद का मॉडल जहाँ केंद्र व राज्य सहमति से निर्णय लेते हैं	भारतीय संविधान
जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई 5 पेट्रोलियम वस्तुएँ	**अनुच्छेद 279क** एवं मानवीय उपभोग की शराब	कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस, और विमान टरबाइन ईंधन	इन्हें जीएसटी में शामिल करने की तिथि जीएसटी परिषद की सिफारिश पर तय होगी; मानवीय शराब संविधानतः बाहर है	भारतीय संविधान		
जीएसटी एमनेस्टी स्कीम (ब्याज व जुर्माना माफी)	जीएसटी अधिनियम की **नई धारा 128क**	वित्त वर्ष **2017–18, 2018–19 और 2019–20** के धारा 73 (गैर-कपटपूर्ण) के मांग नोटिस	मूल कर का भुगतान करने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)		
विभागीय अपील की न्यूनतम मौद्रिक सीमाएँ	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआई) परिपत्र	**जीएसटी: ₹20 लाख** |	**उच्च न्यायालय: ₹1 करोड़** |	**सर्वोच्च न्यायालय: ₹2 करोड़**	छोटे कर विवादों में अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी की समाप्ति	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
जीएसटी के समक्ष अपील हेतु पूर्व-जमा (पूर्व-जमा)	जीएसटी अधिनियम की धारा 112	विवादित कर का **20% से घटाकर 10%** (अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ से घटाकर **₹20 करोड़** प्रत्येक)	और कॉर्पोरेट करदाताओं की कार्यशील पूँजी का अवरोध समाप्त	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)		
फॉर्म जीएसटी-1 एवं बायोमेसूत्र आधार सत्यापन	जीएसटी नेटवर्क (जीएसटी) प्रक्रियात्मक सुधार	एक ही कर अवधि में जीएसटी-3 दाखिल करने से पहले **जीएसटी-1** द्वारा बिक्री विवरण में संशोधन की सुविधा	रिटर्न बेमेल में कमी और फर्जी दावों पर रोक	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)		

क्या आप जानते हैं?: विश्व में सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वर्ष **1954 में फ्रांस** ने लागू किया था, जबकि भारत का **'दोहरा जीएसटी मॉडल' (जीएसटी — जिसमें केंद्र जीएसटी और राज्य जीएसटी एक साथ लगाते हैं) कनाडा के संघीय मॉडल** पर आधारित है (आईयूसी अकादमी)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: 'मानवीय उपभोग के लिए मादक मदिरा' और **'5 पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस,)'** के संवैधानिक अंतर को ध्यान से समझें: मानवीय उपभोग की शराब को संविधान के **अनुच्छेद 366(12क)** में जीएसटी की परिभाषा से ही **स्थायी रूप से बाहर** रखा गया है (अर्थात् इसे जीएसटी में लाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा); जबकि 5 पेट्रोलियम उत्पाद संविधान के तहत जीएसटी में शामिल हैं, किंतु अनुच्छेद 279क के अनुसार उन पर जीएसटी उस तिथि से लागू होगा जिसकी सिफारिश **जीएसटी परिषद** करेगी (इसके लिए किसी नए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है) (भारतीय संविधान)।

★ **स्मरण सूत्र:** जीएसटी में विभागीय अपील की मौद्रिक सीमाएँ और मतदान भार याद रखने का सूत्र — **"वोट में केंद्र 1/3, राज्य 2/3 और पास होने को चाहिए 3/4; और सरकारी अपील की सीमा: जीएसटी में 20 लाख, उच्च न्यायालय में 1 करोड़ और सर्वोच्च न्यायालय में 2 करोड़!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 8: वित्तीय एवं पूँजी बाजार (सेबी सुधार 2026) तथा भारत का बाह्य क्षेत्र — 22.2 करोड़ डीमैट खाते, दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध, 734.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार एवं हरितक्षेत्र विदेशी निवेश

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 8: वित्तीय एवं पूँजी बाजार (सेबी सुधार 2026) तथा भारत का बाह्य क्षेत्र — 22.2 करोड़ डीमैट खाते, दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध, 734.6 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार एवं हरितक्षेत्र विदेशी निवेश

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नवीनतम पूँजी बाजार सुधार एवं आँकड़े (2026 संकलन)	भारत का बाह्य क्षेत्र — 734.6 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व में तीसरा स्थान एवं प्रवासी जमा	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत के पूँजी बाजार एवं बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ीकरण का समग्र चक्र (2026 संकलन)	विशेष परिशिष्ट: संवैधानिक-आर्थिक अंतर्संबंध एवं अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा (अनुसूचित जाति// अनुसूचित जाति/) उच्च-प्राथमिकता विश्लेषण (2026 संकलन)

8.1 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नवीनतम पूँजी बाजार सुधार एवं आँकड़े (2026 संकलन)

• **भारत में डीमैट खातों की संख्या 22.2 करोड़ के पार (सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026):** सेबी (सेबी — 1988 में स्थापित और सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त) के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, भारतीय पूँजी बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी ऐतिहासिक शिखर पर पहुँच गई है। **फरवरी 2026 के अंत तक देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 22.2 करोड़ (222 मिलियन)** पर पहुँच गई, जिसमें **सीडीएसएल (सीडीएसएल — .) के पास 17.8 करोड़ खाते** और **एनएसडीएल (एनएसडीएल — .) के पास 4.4 करोड़ खाते** दर्ज किए गए (अकेले फरवरी 2026 में सीडीएसएल में 23.8 लाख और एनएसडीएल में 4.3 लाख नए शुद्ध डीमैट खाते जुड़े) (सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026)।

• **कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार एवं एमसीएक्स आईकॉमडेक्स सूचकांक में उछाल:** सेबी के आँकड़ों के अनुसार, फरवरी 2026 के अंत में वार्षिक आधार (वार्षिक) पर कमोडिटी समग्र सूचकांक **एमसीएक्स आईकॉमडेक्स ने 69.1 प्रतिशत का रिटर्न** दर्ज किया, जिसका मुख्य चालक **बुलियन (सोना-चाँदी) उप-सूचकांक में दर्ज की गई 101.5 प्रतिशत की ऐतिहासिक तेजी** और धातु सूचकांक में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि रही (सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026)।

• **सेबी के प्रमुख संरचनात्मक सुधार (टी+0 निपटान, म्यूचुअल फंड नेट सेटलमेंट, वायदा एवं विकल्प नियम एवं बेस मिनिमम कैपिटल):**

1. **टी+1 के बाद वैकल्पिक टी+0 (उसी दिन निपटान) चक्र:** भारत संपूर्ण शेयर बाजार में **टी+1** निपटान चक्र लागू करने वाला विश्व का अग्रणी बड़ा बाजार बनने के बाद अब चुनिंदा प्रतिभूतियों में **वैकल्पिक टी+0 (उसी दिन शाम तक शेयर और धन का निपटान)** चक्र भी लागू कर चुका है (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी))।

2. **म्यूचुअल फंड योजनाओं हेतु 'नेट सेटलमेंट' फ्रेमवर्क एवं प्रमुख सर्कुलर:** सेबी ने कैश सेगमेंट में म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा किए गए लेन-देन के लिए फंडों के **शुद्ध निपटान (शुद्ध निपटान)** का फ्रेमवर्क जारी किया है तथा 9 फरवरी 2026 को म्यूचुअल फंडों और रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंटों के लिए अद्यतन प्रमुख सर्कुलर जारी किए हैं (सेबी परिपत्र पोर्टल)।

3. **नया एसेट क्लास (— ₹10 लाख न्यूनतम निवेश) एवं वायदा एवं विकल्प सुरक्षा उपाय:** म्यूचुअल फंड (खुदरा निवेश) और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रधानमंत्री — ₹50 लाख न्यूनतम निवेश) के बीच के अंतर को भरने के लिए सेबी ने उच्च जोखिम लेने की क्षमता वाले निवेशकों हेतु **न्यूनतम ₹10 लाख प्रति निवेशक** की सीमा के साथ एक नया विनियमित एसेट क्लास शुरू किया है। साथ ही, खुदरा निवेशकों को सट्टेबाजी के भारी नुकसान से बचाने के लिए इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स (वायदा एवं विकल्प) में न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को ₹5–10 लाख से बढ़ाकर **₹15 लाख** किया गया है और प्रति एक्सचेंज केवल एक साप्ताहिक इंडेक्स एक्सपायरी को मान्यता दी गई है (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी))।

4. **निष्क्रिय सदस्यों को बेस मिनिमम कैपिटल (न्यूनतम आधार पूँजी) की वापसी (अगस्त 2026 परामर्श पत्र):** सेबी के अगस्त 2026 के निपटान एवं जोखिम प्रबंधन दस्तावेज के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 12 महीनों से निष्क्रिय सदस्यों को **₹1 लाख से अधिक के अतिरिक्त बेस मिनिमम कैपिटल (न्यूनतम आधार पूँजी)** को वापस करने की शर्तें (कोई लंबित निवेशक शिकायत या मध्यस्थता मामला न होना तथा सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना) निर्धारित की गई हैं (सेबी परामर्श पत्र — अगस्त 2026)।

8.2 भारत का बाह्य क्षेत्र — 734.6 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व में तीसरा स्थान एवं प्रवासी जमा

• **भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 734.6 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर (अक्टूबर 2026):** भारतीय रिजर्व बैंक की 7 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, **2 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 734.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन)** पर पहुँच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के **4 घटक** होते हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (— विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, सबसे बड़ा घटक), स्वर्ण भंडार,

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास विशेष आहरण अधिकार (विशेष आहरण अधिकार), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (रिजर्व ट्रेंच पोजीशन) (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में उछाल और ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर:

1. **सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 20.6% की वृद्धि (अप्रैल–अगस्त 2026–27):** वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल–अगस्त के दौरान भारत में **सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह) में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज की गई, जबकि भारत से बाहर जाने वाला शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) एक वर्ष पूर्व के 14.0 बिलियन से बढ़कर **17.7 बिलियन** हो गया (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

2. **वैश्विक ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में भारत को तीसरा स्थान (41.3 बिलियन):** अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान विश्व स्तर पर घोषित **ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश — जहाँ विदेशी कंपनी भारत में शून्य से नई उत्पादन इकाई या फैक्ट्री स्थापित करती है)** के मामले में भारत **41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 41.3 बिलियन)** की राशि के साथ **विश्व में तीसरे स्थान** पर रहा (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

• अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार) एवं विश्व व्यापार परिदृश्य:

1. **अनिवासी जमा और बाह्य वाणिज्यिक उधार में वृद्धि:** अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान अनिवासी जमाओं (- — (ख), संशोधित अनुमान,) के अंतर्गत शुद्ध अंतर्वाह तेजी से बढ़कर गया तथा भारत को **सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार)** एक वर्ष पूर्व के 17.0 बिलियन से बढ़कर **23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 23.9 बिलियन)** हो गया (पुनर्भुगतान समायोजित करने के बाद शुद्ध बाह्य वाणिज्यिक उधार अंतर्वाह 4.7 बिलियन से बढ़कर **7.3 बिलियन** रहा) (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

2. **आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डब्ल्यूईओ — जुलाई 2026):** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जुलाई 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, विश्व वस्तु और सेवा व्यापार की मात्रा वृद्धि वर्ष 2025 के 5.0 प्रतिशत से नरम होकर वर्ष 2026 में **3.5 प्रतिशत** रहने का अनुमान है (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

8.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारत के पूँजी बाजार एवं बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ीकरण का समग्र चक्र (2026 संकलन)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: घरेलू बचत का वित्तीयकरण — 22.2 करोड़ डीमैट खाते (17.8 करोड़ सीडीएसएल + 4.4 करोड़ एनएसडीएल) एवं के माध्यम से रिकॉर्ड खुदरा निवेश

चरण 2
चरण 2: सेबी के आधुनिक बाजार सुधार — वैकल्पिक टी+0 निपटान चक्र, म्यूचुअल फंड नेट सेटलमेंट एवं वायदा एवं विकल्प में ₹15 लाख कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा

चरण 3
चरण 3: बाह्य पूँजी का मजबूत अंतर्वाह — अप्रैल–अगस्त 2026 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 20.6% वृद्धि, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 41.3 बिलियन के साथ विश्व में तीसरा स्थान व 23.9 बिलियन सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार

चरण 4
चरण 4: 2 अक्टूबर 2026 को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 734.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन) के सुदृढ़ स्तर पर पहुँचना]`

8.4 तुलनात्मक सारणी: सेबी (सेबी) पूँजी बाजार आँकड़े एवं आरबीआई (आरबीआई) बाह्य क्षेत्र संकेतक (2026 संकलन)

वित्तीय बाजार / बाह्य क्षेत्र संकेतक	पूर्ववर्ती तुलनात्मक आँकड़ा	नवीनतम आधिकारिक आँकड़ा	प्रमुख विश्लेषणात्मक तथ्य एवं रैंकिंग	आधिकारिक सत्यापन स्रोत	
कुल डीमैट खाते	जनवरी 2026 की तुलना में +1.3% -- वृद्धि	**22.2 करोड़ (फरवरी 2026 के अंत में)**	**सीडीएसएल: 17.8 करोड़ खाते **	**एनएसडीएल: 4.4 करोड़ खाते**	सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026
एमसीएक्स आईकॉमडेक्स समग्र कमोडिटी सूचकांक रिटर्न	ऊर्जा सूचकांक में -3.5% वार्षिक की गिरावट	**+69.1% वार्षिक वृद्धि (फरवरी 2026 वार्षिक)**	बुलियन (सोना-चाँदी) सूचकांक में **+101.5%** और धातु सूचकांक में **+19.3%** की रैली	सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026	
भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार	बाह्य झटकों के विरुद्ध सुरक्षा कवच	**अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन (2 अक्टूबर 2026 को)**	4 घटक: विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (विदेशी मुद्रा आस्तियाँ), स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (रिजर्व ट्रेंच पोजीशन)	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026	

वित्तीय बाजार / बाह्य क्षेत्र संकेतक	पूर्ववर्ती तुलनात्मक आँकड़ा	नवीनतम आधिकारिक आँकड़ा	प्रमुख विश्लेषणात्मक तथ्य एवं रैंकिंग	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
वैश्विक ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में भारत की रैंक	नई विनिर्माण व डिजिटल परियोजनाओं की घोषणा	**विश्व में तीसरा स्थान (अमेरिकी डॉलर 41.3 बिलियन, अप्रैल–अगस्त 2026)**	अप्रैल–अगस्त 2026–27 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में **20.6% की वृद्धि**	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026
बाह्य वाणिज्यिक उधार (& बाह्य वाणिज्यिक उधार)	अप्रैल–अगस्त 2025: सकल 17.0 बिलियन (शुद्ध 4.7 बिलियन)	**सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार: अमेरिकी डॉलर 23.9 बिलियन (शुद्ध: अमेरिकी डॉलर 7.3 बिलियन, अप्रैल–अगस्त 2026)**	भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अवसंरचना व विस्तार हेतु विदेशी ऋण का उच्च उपयोग	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026
विश्व वस्तु एवं सेवा व्यापार वृद्धि (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डब्ल्यूईओ जुलाई 2026)	वर्ष 2025 में 5.0% वैश्विक व्यापार वृद्धि	**वर्ष 2026 में 3.5% अनुमानित**	वैश्विक व्यापार में नरमी के बावजूद भारत के घरेलू और सेवा क्षेत्र का लचीला प्रदर्शन	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026

क्या आप जानते हैं?: ग्रीनफील्ड एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और **ब्राउनफील्ड एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)** में यह अंतर है कि ग्रीनफील्ड निवेश में कोई विदेशी कंपनी मेजबान देश (भारत) में बिल्कुल नए सिरे से नई फैक्ट्री, संयंत्र या कार्यालय का निर्माण करती है (जिससे नई उत्पादन क्षमता और नए रोजगार सीधे सृजित होते हैं — इसमें भारत अप्रैल–अगस्त 2026 में 41.3 बिलियन के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर रहा), जबकि ब्राउनफील्ड निवेश में विदेशी कंपनी किसी पहले से चल रही भारतीय कंपनी के शेयर खरीदती है या उसका विलय/अधिग्रहण करती है (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के चार घटकों पर अक्सर यह ट्रैप प्रश्न पूछा जाता है कि क्या **'विशेष आहरण अधिकार' (विशेष आहरण अधिकार — , जिसे 'पेपर गोल्ड' भी कहते हैं)** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) की कोई मुद्रा है? याद रखें कि **विशेष आहरण अधिकार कोई मुद्रा नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर कोई दावा है,** बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य **5 प्रमुख मुद्राओं की टोकरी (5 : अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर, यूरो , चीनी रॅन्मिन्बी , जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग)** पर आधारित एक आरक्षित अंतर्राष्ट्रीय लेखा इकाई है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

★ **स्मरण सूत्र:** वर्ष 2026 के पूँजी बाजार और बाह्य क्षेत्र के 5 शिखर आँकड़ों का सूत्र — **"डीमैट खाते 22.2 करोड़ (सीडीएसएल 17.8 + एनएसडीएल 4.4), फॉरेक्स रिजर्व 734.6 बिलियन, ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 41.3 बिलियन के साथ भारत दुनिया में नंबर-3, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 20.6% उछाल, और सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार 23.9 बिलियन!"** (आईयूसी अकादमी)।

8.5 विशेष परिशिष्ट: संवैधानिक-आर्थिक अंतर्संबंध एवं अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा (अनुसूचित जाति//अनुसूचित जाति/) उच्च-प्राथमिकता विश्लेषण (2026 संकलन)

• केंद्रीय बजट प्रक्रिया एवं संसदीय नियंत्रण का समग्र अनुक्रम (अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 117):

1. **बजट की प्रस्तुति:** अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष 'वार्षिक वित्तीय विवरण' रखवाते हैं (भारतीय संविधान)।

2. **आम बहस:** प्रस्तुति के कुछ दिनों बाद दोनों सदनों में बजट के समग्र सिद्धांतों पर 3–4 दिनों तक चर्चा होती है; इस चरण में कोई मतदान नहीं होता (भारतीय संविधान)।

3. **विभागीय स्थायी समितियों (24 अनुसूचित जातियों) द्वारा जाँच:** सदन स्थगित रहता है और 24 विभागीय स्थायी समितियाँ (प्रत्येक में 31 सदस्य = 21 लोकसभा + 10 राज्यसभा) विभिन्न मंत्रालयों की **अनुदान की मांगों** की सूक्ष्म जाँच कर अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं (भारतीय संविधान)।

4. **अनुदान की मांगों पर मतदान (— अनुच्छेद 113):** यह अनन्य शक्ति **केवल लोकसभा** के पास है (राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं)। इस दौरान सांसद तीन प्रकार के **कटौती प्रस्ताव** ला सकते हैं — **नीतिगत कटौती प्रस्ताव (: मांग की राशि घटाकर ₹1 करना), मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (: मांग में एक निर्दिष्ट राशि की कमी करना),** और **सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (: किसी विशेष शिकायत को उठाने हेतु मांग में ₹100 की कमी करना)**। अंतिम दिन शेष सभी मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखने की प्रक्रिया को **'गिलोटिन'** कहा जाता है (आईयूसी अकादमी)।

5. **विनियोग विधेयक (— अनुच्छेद 114):** भारत की संचित निधि (— अनुच्छेद 266) से एक भी रुपया विनियोग अधिनियम पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता (भारतीय संविधान)।

6. **वित्त विधेयक (— अनुच्छेद 110 एवं 117):** आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के कर प्रस्तावों (शेयर बायबैक कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर सुधार, सीमा शुल्क परिवर्तन आदि) को वैधानिक रूप देने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसे **अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (कर , 1931)** के अनुसार बजट प्रस्तुत होने के **75 दिनों के भीतर** संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **राजकोषीय घाटे के चारों प्रमुख प्रकारों का सूत्रबद्ध संकलन:**

1. **राजस्व घाटा:** \{राजस्व घाटा} = \{कुल राजस्व व्यय} - \{कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)} (जब सरकार की अपनी नियमित आय उसके प्रशासनिक व रखरखाव खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो) (राजकोषीय नीति विवरण)।

2. **प्रभावी राजस्व घाटा:** \{प्रभावी राजस्व घाटा} = \{राजस्व घाटा} - \{पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान} (इसे रंगराजन समिति की सिफारिश पर वर्ष 2011–12 के बजट से शुरू किया गया था) (राजकोषीय नीति विवरण)।

3. **राजकोषीय घाटा (— सरकार की कुल उधार आवश्यकता):** \{राजकोषीय घाटा} = \{कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)} - (\{राजस्व प्राप्तियाँ} + \{ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ}) (बजट 2026–27 में यह जीडीपी का **4.3%** है, जबकि संशोधित अनुमान 2025–26 में **4.4%** रहा) (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

4. **प्राथमिक घाटा:** \{प्राथमिक घाटा} = \{राजकोषीय घाटा} - \{ब्याज अदायगियाँ} (यह दर्शाता है कि पिछले ऋणों के ब्याज भुगतान को हटाने के बाद वर्तमान वर्ष की उधार आवश्यकता कितनी है) (राजकोषीय नीति विवरण)।

5. **मौद्रिकृत घाटा:** वह हिस्सा जिसकी पूर्ति आरबीआई द्वारा नई मुद्रा छापकर या प्राथमिक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदकर की जाती है (1997 के 'अर्थोपाय अग्रिम' — समझौते और अधिनियम, 2003 द्वारा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्राथमिक बाजार में आरबीआई की भागीदारी पर रोक लगाई गई है) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक व आधुनिक समितियाँ:**

• **नरसिम्हम समिति- एवं नरसिम्हम समिति-:** बैंकिंग क्षेत्र सुधार, एसएलआर/सीआरआर में कमी, 4-स्तरीय बैंकिंग ढाँचा, पूँजी पर्याप्तता (पूँजी पर्याप्तता अनुपात) और अधिनियम की आधारशिला (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **उर्जित पटेल समिति:** मौद्रिक नीति ढाँचे का सुदृढ़ीकरण, को मुख्य मुद्रास्फीति सूचकांक बनाना, 4% ± 2% का लचीला मुद्रास्फीति लक्षीकरण और 6-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **पी.जे. नायक समिति:** भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा और **बैंक बोर्ड ब्यूरो (बैंक बोर्ड ब्यूरो)** का गठन (जिसे अब **'वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो' — वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो** में रूपांतरित कर दिया गया है जो और सार्वजनिक वित्तीय/बीमा संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति की सिफारिश करता है) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **नचिकेत मोर समिति (2013–14):** छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएँ; **भुगतान बैंक** की स्थापना की सिफारिश (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **उषा थोराट समिति: लघु वित्त बैंकों (— लघु वित्त बैंकों)** के लाइसेंस आवेदनों की जाँच और मूल्यांकन (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **एन.के. सिंह समिति (2016–17):** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा और ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी) को प्रमुख मध्यावधि राजकोषीय एंकर बनाने की सिफारिश (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

• **बिमल जालान समिति (2018–19):** आरबीआई के **'आर्थिक पूँजी ढाँचे' (रूपरेखा —)** की समीक्षा और आकस्मिक जोखिम बफर को आरबीआई की बैलेंस शीट के **5.5% से 6.5%** के बीच रखकर अधिशेष लाभ सरकार को हस्तांतरित करने का सूत्र (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **टी.के. विश्वनाथन समिति:** कॉर्पोरेट दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का प्रारूपण (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **नंदन नीलेकणी समिति:** भारत में डिजिटल भुगतान को गहरा करने और 247 / तथा पीआईडीएफ कोष की स्थापना की सिफारिश (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• **के.वी. कामथ समिति:** कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त कॉर्पोरेट ऋणों के समाधान हेतु 26 क्षेत्रों के वित्तीय मापदंडों का निर्धारण (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

8.7 समग्र विश्लेषणात्मक सार-संग्रह: वर्ष 2026 के संवैधानिक, न्यायिक, विधायी एवं राजकोषीय मानक

• **वर्ष 2026 के संवैधानिक एवं न्यायिक मानक — गहन तुलनात्मक संश्लेषण:**

1. **भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद का उत्तराधिकार अनुक्रम (अनुच्छेद 124(2)):** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 124(2)** और द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में स्थापित परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है:

• **50वें मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (9 नवंबर 2022 से 10 2026 संकलन तक) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **51वें मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (11 2026 संकलन से 13 मई 2025 तक) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **52वें मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई (14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **53वें मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सूर्य कांत** (24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण; 9 फरवरी 2027 तक 15 माह का कार्यकाल) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

2. **सर्वोच्च न्यायालय की चार ऐतिहासिक 9-न्यायाधीश संविधान पीठों का न्यायशास्त्र:**

• **मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (जुलाई–2026 संकलन, 8:1 बहुमत): **राज्य सूची की** प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 50** के तहत खनिज-युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की विधायी शक्ति को वैध ठहराया तथा स्पष्ट किया कि खनन रॉयल्टी कर नहीं है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन, 8:1 बहुमत): **राज्य सूची की** प्रविष्टि 8 ('नशीली मदिरा') **के अंतर्गत** औद्योगिक अल्कोहल** को शामिल मानते हुए राज्यों के नियामक और कराधान अधिकार को पुष्ट किया (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन, 8:1 बहुमत): **निर्णय दिया कि नागरिकों की प्रत्येक निजी संपत्ति स्वतः** अनुच्छेद 39(ख) के अंतर्गत 'समुदाय का भौतिक संसाधन'** नहीं बन जाती (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के तहत 'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश पीठ निर्णय (20 अगस्त 2026):** 48 वर्ष पुराने बैंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा (1978) संदर्भ का निपटारा करते हुए राज्य के संप्रभु कार्यों और व्यवस्थित आर्थिक उद्यमों के बीच की सीमा स्पष्ट की (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

3. **विधायी गैर-आपराधीकरण तुलना — जन विश्वास अधिनियम, 2023 बनाम जन विश्वास अधिनियम, 2026:**

• **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023:** 19 मंत्रालयों के **42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों** को अपराध-मुक्त किया गया (पत्र सूचना कार्यालय)।

• **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (अप्रैल 2026 में पारित):** 23 मंत्रालयों के **79–80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों** में संशोधन कर **717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक** बनाया गया, प्रथम अपराध पर चेतावनी, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत सुधार नोटिस और प्रत्येक तीन वर्ष में जुर्माने में 10 प्रतिशत स्वतः संशोधन की व्यवस्था लागू की गई (पत्र सूचना कार्यालय)।

विश्लेषणात्मक क्षेत्र	संवैधानिक / वैधानिक आधार	वर्ष 2026 का सत्यापित आधिकारिक मानक	प्रमुख संस्थागत एवं आर्थिक प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
केंद्रीय बजट 2026–27 कुल व्यय	अनुच्छेद 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण)	**₹53,47,315 करोड़** (जीडीपी का 13.6%; संशोधित अनुमान पर +7.7% वृद्धि)	प्रभावी सार्वजनिक पूँजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ से अधिक	केंद्रीय बजट
केंद्रीय बजट 2026–27 कुल प्राप्तियाँ	भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266(1))	ऋण-भिन्न प्राप्तियाँ **₹36,51,547 करोड़** (केंद्र का शुद्ध कर राजस्व **₹28.67 लाख करोड़**)	सकल बाजार उधार ₹17.2 लाख करोड़; शुद्ध बाजार उधार ₹11.7 लाख करोड़	केंद्रीय बजट
राजकोषीय एवं राजस्व घाटा (2026–27)	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003	**राजकोषीय घाटा: जीडीपी का 4.3%** (संशोधित 4.4%) \	**राजस्व घाटा: 1.5%**	केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात 56.1% से घटकर **55.6%** अनुमानित	केंद्रीय बजट
आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 परिदृश्य	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	**वित्त वर्ष 2025–26 वास्तविक जीडीपी वृद्धि: 7.4%** \	**2026–27 अनुमान: 6.8%–7.2%**	मध्यम-अवधि संभावित वृद्धि ~7%; वैश्विक नवाचार सूचकांक में **38वाँ स्थान**	केंद्रीय बजट
16वाँ वित्त आयोग (2026–31)	अनुच्छेद 280 (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया)	**41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी** \	**₹9.47 लाख करोड़ कुल 5-वर्षीय अनुदान**	क्षैतिज सूत्र: आय अंतराल 42.5%, जनसंख्या 17.5%, जनसांख्यिकी 10%, क्षेत्रफल 10%, वन 10%, **जीडीपी योगदान 10%**	केंद्रीय बजट

विश्लेषणात्मक क्षेत्र	संवैधानिक / वैधानिक आधार	वर्ष 2026 का सत्यापित आधिकारिक मानक	प्रमुख संस्थागत एवं आर्थिक प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
63वीं आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक (अक्टूबर 2026)	धारा 45यख, आरबीआई अधिनियम, 1934 (गवर्नर संजय मल्होत्रा)	**रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50%** (स्थायी जमा सुविधा 5.25%, बैंक दर 5.75%)	4% ± 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर मूल्य स्थिरता एवं वृद्धि संतुलन	भारतीय रिजर्व बैंक
57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026)	अनुच्छेद 279क (अध्यक्ष: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण)	**अभियोजन सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़** |	अधिकतम सामान्य दंड **₹10,000**	विश्वास-आधारित कर प्रशासन एवं त्वरित स्वचालित रिफंड प्रणाली	पत्र सूचना कार्यालय
सेबी पूँजी बाजार सुधार (2026)	सेबी अधिनियम, 1992 (अध्यक्ष: तुहिन कांत पांडे)	**22.2 करोड़ डीमैट खाते** |	**दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध** |	वैकल्पिक **टी+0 निपटान**	संस्थागत हेजिंग को प्रोत्साहन और खुदरा निवेशक संरक्षण (₹15 लाख न्यूनतम अनुबंध)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एनपीसीआई डिजिटल भुगतान (2026)	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	**यूपीआई लाइट (< ₹1,000, ₹5,000 वॉलेट)** |	**यूपीआई सर्कल (₹15,000/माह)**	समेकित यूपीआई परिपत्र (18 सितंबर 2026); ग्राहकों और ₹2,000 तक के भुगतान पर शून्य शुल्क	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

हल सहित बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न (45 हल सहित अभ्यास प्रश्न — द्वितीय खंड)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **केंद्रीय बजट 2026–27 के अनुसार, बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में केंद्र सरकार का कुल व्यय कितने लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है?**
(क) ₹47.65 लाख करोड़
(ख) ₹49.65 लाख करोड़
(ग) ₹51.20 लाख करोड़
(घ) ₹53.47 लाख करोड़
उत्तर: (घ)
व्याख्या: केंद्रीय बजट 2026–27 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार, बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में संघ सरकार का कुल व्यय **₹53.47 लाख करोड़** (जीडीपी का 13.6 प्रतिशत) अनुमानित है, जो संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 के **₹49.65 लाख करोड़** पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **केंद्रीय बजट 2026–27 में संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 और बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का क्रमशः कितना प्रतिशत रखा गया है?**
(क) 4.8% और 4.5%
(ख) 4.4% और 4.3%
(ग) 4.5% और 4.1%
(घ) 4.9% और 4.4%
उत्तर: (ख)
व्याख्या: वित्त मंत्री के बजट भाषण 2026–27 के अनुसार, संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के **4.4 प्रतिशत** पर रहा और ऋण समेकन पथ के अनुरूप बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का **4.3 प्रतिशत** अनुमानित है (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **केंद्रीय बजट 2026–27 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2030–31 तक अपने ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी) को घटाकर किस स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है?**
(क) 40±1 प्रतिशत
(ख) 45±1 प्रतिशत
(ग) 50±1 प्रतिशत
(घ) 60±1 प्रतिशत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकृत मानकों की ओर बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने **वर्ष 2030–31 तक ऋण-जीडीपी अनुपात को जीडीपी के 50± 1 प्रतिशत** पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **केंद्रीय बजट 2026–27 के अनुसार, केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी) संशोधित अनुमान 2025–26 के 56.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2026–27 में घटकर कितना रहने का अनुमान है?**
(क) 54.2 प्रतिशत
(ख) 55.6 प्रतिशत
(ग) 56.8 प्रतिशत
(घ) 52.5 प्रतिशत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बजट 2026–27 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, ऋण-जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025–26 के **56.1 प्रतिशत** की तुलना में **बजट अनुमान 2026–27 में जीडीपी का 55.6 प्रतिशत** रहने का अनुमान है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ) और केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व (कर) क्रमशः कितना अनुमानित है?**
(क) ₹35.33 लाख करोड़ और ₹28.67 लाख करोड़
(ख) ₹34.00 लाख करोड़ और ₹26.70 लाख करोड़
(ग) ₹38.50 लाख करोड़ और ₹30.10 लाख करोड़
(घ) ₹32.15 लाख करोड़ और ₹25.40 लाख करोड़
उत्तर: (क)
व्याख्या: बजट अनुमान 2026–27 में संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ **₹35.33 लाख करोड़** अनुमानित हैं, जिनमें केंद्र को प्राप्त शुद्ध कर राजस्व **₹28.67 लाख करोड़** और गैर-कर राजस्व **₹6.66 लाख करोड़** शामिल है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में 'पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता' (अनुसूचित जाति) योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कितने लाख करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है?**
(क) ₹1.0 लाख करोड़
(ख) ₹1.5 लाख करोड़
(ग) ₹2.0 लाख करोड़
(घ) ₹2.5 लाख करोड़
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बजट अनुमान 2026–27 में केंद्र के पूँजीगत व्यय (जीडीपी का 3.1%) के अंतर्गत **अनुसूचित जाति** के माध्यम से राज्यों को पूँजीगत सहायता हेतु **₹2.0 लाख करोड़** का परिव्यय रखा गया है (राजकोषीय नीति विवरण — बजट 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

7. **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 (2025–26) के अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (जीडीपी) कितने प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है?**
(क) 6.0% से 6.5%
(ख) 6.3% से 6.8%
(ग) 6.8% से 7.2%
(घ) 7.5% से 8.0%
उत्तर: (ग)
व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के आधिकारिक इन्फोग्राफिक्स व मुख्य बिंदुओं के अनुसार, मजबूत घरेलू वृद्धि गति के बल पर **वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8 से 7.2 प्रतिशत (6.8% – 7.2%)** की दर से बढ़ने का अनुमान है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

8. **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, केंद्र सरकार का 'प्रभावी पूँजीगत व्यय' (प्रभावी पूँजीगत व्यय जीडीपी) महामारी-पूर्व के 2.7% के औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) में जीडीपी के कितने प्रतिशत पर पहुँच गया?**
(क) 3.1 प्रतिशत
(ख) 3.5 प्रतिशत
(ग) 4.0 प्रतिशत
(घ) 4.8 प्रतिशत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, जीडीपी के अनुपात में केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय महामारी-पूर्व के 2.7% के औसत से बढ़कर **वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 में जीडीपी के 4 प्रतिशत** पर पहुँच गया है, जबकि राज्यों ने अपना कैपेक्स जीडीपी के **2.4%** पर बनाए रखा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 प्रमुख बिंदु)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

9. **केंद्रीय बजट 2026–27 में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए 'शेयर बायबैक' (अंश पुनर्खरीद) पर किस रूप में कर लगाने का प्रावधान किया गया है?**
(क) इसे पूर्णतः कर-मुक्त (कर) कर दिया गया है
(ख) इसे 'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ) के रूप में कर योग्य बनाया गया है (प्रवर्तकों पर अतिरिक्त बायबैक कर सहित)
(ग) इसे कृषि आय के समतुल्य माना गया है
(घ) इस पर केवल 1% स्रोत पर कर कटौती लागू होगी
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बजट 2026–27 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए शेयर बायबैक पर **'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ)** के रूप में कर लगाया जाएगा, जबकि प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) को अतिरिक्त बायबैक कर देना होगा (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

10. **केंद्रीय बजट 2026–27 के कर प्रस्तावों के अनुसार, नई कर व्यवस्था (कर) में कंपनियों को अपने उपलब्ध 'न्यूनतम वैकल्पिक कर' (न्यूनतम वैकल्पिक कर) क्रेडिट से कर देयता के किस हिस्से तक सेट-ऑफ (समायोजन) करने की अनुमति दी गई है?**
(क) कर देयता के 1/10वें भाग तक
(ख) कर देयता के एक-चौथाई भाग तक
(ग) कर देयता के आधे भाग तक
(घ) कर देयता के 100 प्रतिशत तक
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बजट 2026–27 में न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर (कर) बनाने का प्रस्ताव किया गया है और नई कर व्यवस्था में कर देयता के **एक-चौथाई की सीमा तक उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट का उपयोग कर सेट-ऑफ** की अनुमति दी गई है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

11. **केंद्रीय बजट 2026–27 में कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कितनी दवाओं या औषधियों को मूल सीमा शुल्क (— मूल सीमा शुल्क) से पूर्ण छूट प्रदान की गई है?**
(क) 5 दवाओं को
(ख) 10 दवाओं को
(ग) 17 दवाओं को
(घ) 25 दवाओं को
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बजट 2026–27 में कैंसर रोगियों के उपचार में काम आने वाली **17 दवाओं या औषधियों** को मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क) से पूर्णतः मुक्त किया गया है (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

12. **केंद्रीय बजट 2026–27 की घोषणा के अनुसार, व्यापार सुगमता के लिए 'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम' (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) को कितने वर्षों में लागू किया जाएगा?**
(क) 1 वर्ष में
(ख) 2 वर्षों में
(ग) 5 वर्षों में
(घ) 7 वर्षों में
उत्तर: (ख)
व्याख्या: कार्गो क्लीयरेंस अनुमोदन हेतु एकल डिजिटल विंडो के साथ **'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम' (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) को आगामी 2 वर्षों में रोलआउट** किया जाएगा (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

13. **भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा जून 2025 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में सभी बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में चरणबद्ध रूप से कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की गई?**
(क) 25 आधार अंक
(ख) 50 आधार अंक
(ग) 100 आधार अंक (1 प्रतिशत)
(घ) 150 आधार अंक
उत्तर: (ग)
व्याख्या: 6 जून 2025 को गवर्नर संजय मल्होत्रा के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार, आरबीआई ने सभी बैंकों के **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में चरणबद्ध तरीके से 100 आधार अंकों (100 आधार अंक)** की कटौती की अधिसूचना जारी की (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

14. **अक्टूबर 2026 की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) दर और बैंक दर किस स्तर पर निर्धारित रही?**
(क) 5.25 प्रतिशत
(ख) 5.75 प्रतिशत
(ग) 6.50 प्रतिशत
(घ) 6.75 प्रतिशत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: आरबीआई की 7 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, **सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत** पर निर्धारित रही (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

15. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2025 में जारी परिपत्र के अनुसार, आयातक बिना किसी बैंक गारंटी या अपरिवर्तनीय स्टैंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट के 'शिपिंग पोत' के आयात के लिए कितनी राशि तक अग्रिम विप्रेषण कर सकते हैं?**
(क) 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक
(ख) 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक
(ग) 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 50 मिलियन) तक
(घ) 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक
उत्तर: (ग)
व्याख्या: 13 जून 2025 के आरबीआई परिपत्र के तहत आयातकों को शिपिंग जहाजों के आयात हेतु बिना बैंक गारंटी के **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 50 मिलियन)** तक का अग्रिम विप्रेषण करने की छूट दी गई है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

16. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित वित्तीय मानदंडों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को न्यूनतम निवल मालियत और अधिकतम निवल एनपीए (शुद्ध एनपीए) अनुपात कितना होना चाहिए?**
(क) न्यूनतम निवल मालियत ₹100 करोड़; शुद्ध एनपीए अधिकतम 3%
(ख) न्यूनतम निवल मालियत ₹50 करोड़; शुद्ध एनपीए अधिकतम 5% (तथा न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9% और पिछले 2 वर्षों में शुद्ध लाभ)
(ग) न्यूनतम निवल मालियत ₹200 करोड़; शुद्ध एनपीए अधिकतम 2%
(घ) न्यूनतम निवल मालियत ₹25 करोड़; शुद्ध एनपीए अधिकतम 7%
उत्तर: (ख)
व्याख्या: आरबीआई द्वारा संशोधित मानदंडों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पात्रता हेतु न्यूनतम नेटवर्थ ₹100 करोड़ से घटाकर **₹50 करोड़ या अधिक**, न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात **9 प्रतिशत**, अधिकतम शुद्ध एनपीए अनुपात **5 प्रतिशत से अनधिक** और ठीक **पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ** निर्धारित किया गया है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

17. **भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' (पीआईडीएफ) योजना का विस्तार करते हुए जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय योजना के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया है?**
(क) पीएम विश्वकर्मा योजना (प्रधानमंत्री)
(ख) पीएम उज्ज्वला योजना
(ग) पीएम फसल बीमा योजना
(घ) पीएम मातृ वंदना योजना
उत्तर: (क)
व्याख्या: आरबीआई ने पीआईडीएफ योजना का विस्तार करते हुए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए **पीएम विश्वकर्मा योजना** के लाभार्थियों को भी पीआईडीएफ योजना के अंतर्गत शामिल किया है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

18. **भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सरकारी प्रतिभूति निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत बढ़ी हुई 23% की 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (परिपक्वता तक धारित) सीमा को चरणबद्ध तरीके से घटाकर शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ के कितने प्रतिशत पर पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है?**
(क) 15.0 प्रतिशत
(ख) 18.0 प्रतिशत
(ग) 19.5 प्रतिशत
(घ) 21.5 प्रतिशत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: महामारी के दौरान 23% की गई परिपक्वता तक धारित सीमा को 2026 संकलन को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से **19.5 प्रतिशत** पर बहाल करने का प्रावधान किया गया है (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

19. **विभिन्न बैंकों में पड़े लावारिस जमा (— 10 वर्ष या अधिक से निष्क्रिय खाते) को नागरिकों द्वारा एक ही स्थान पर खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत वेब पोर्टल का नाम क्या है?**
(क) प्रवाह (प्रवाह)
(ख) उद्गम (उद्गम)
(ग) दक्ष (दक्ष)
(घ) सचेत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: उद्गम (उद्गम — :) पोर्टल नागरिकों को अनेक बैंकों में अपने लावारिस जमा खातों को खोजने की सुविधा देता है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

20. **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, 'यूपीआई लाइट' (यूपीआई लाइट) को कितने रुपये से कम के कम-मूल्य वाले लेन-देन को बिना पिन और त्वरित तरीके से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है?**
(क) ₹200 से कम
(ख) ₹500 से कम
(ग) ₹1,000 से कम (₹1,000)
(घ) ₹5,000 से कम
उत्तर: (ग)
व्याख्या: एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, **यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)** को **₹1,000 से कम (₹1,000)** के कम मूल्य के लेन-देन को बिना पिन के तेज गति से पूरा करने के लिए बनाया गया है तथा इसके वॉलेट की कुल सीमा ₹5,000 है (**एनपीसीआई — यूपीआई लाइट**)।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

21. *एनपीसीआई द्वारा वित्त वर्ष 2026–27 में जारी परिपत्र (यूपीआई परिचालन परिपत्र 242) के अनुसार, छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) के बीच यूपीआई स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी नई योजना शुरू की गई है?*
(क) यूपीआई व्यापार सक्षम योजना (यूपीआई)
(ख) यूपीआई समृद्धि योजना
(ग) यूपीआई महा-व्यापार योजना
(घ) डिजिटल दुकानदार मित्र योजना
उत्तर: (क)
व्याख्या: एनपीसीआई ने परिपत्र यूपीआई | परिचालन परिपत्र 242 | वित्त वर्ष 26-27 के तहत छोटे व्यापारियों में यूपीआई स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करने के लिए **'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना' (यूपीआई)** शुरू की है (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

22. *एनपीसीआई के परिपत्र यूपीआई परिचालन परिपत्र संख्या 227 (वित्त वर्ष 2026–27) के अंतर्गत यूपीआई भुगतानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से संचालित ग्राहक सहायता प्रणाली (यूपीआई सहायता 2.0) को क्या नाम दिया गया है?*
(क) डिजि-सहायक
(ख) माई-यूपीआई ("यूपीआई" — कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूपीआई)
(ग) एनपीसीआई सारथी
(घ) पे-मित्र एआई
उत्तर: (ख)
व्याख्या: एनपीसीआई के परिपत्र यूपीआई परिचालन परिपत्र संख्या 227 के अंतर्गत यूपीआई भुगतानों के लिए एआई-संचालित सहायता (यूपीआई सहायता 2.0) को **"यूपीआई" (माई-यूपीआई)** नाम दिया गया है (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

23. **एनपीसीआई की किस यूपीआई सुविधा के माध्यम से एक प्राथमिक बैंक खाताधारक अपने परिवार के सदस्यों या वरिष्ठ नागरिकों (द्वितीयक उपयोगकर्ताओं) को अपने खाते से निर्धारित सीमा (पूर्ण प्रत्यायोजन में ₹15,000 मासिक तक) के भीतर भुगतान करने का अधिकार दे सकता है?**
(क) यूपीआई लाइट एक्स
(ख) यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)
(ग) यूपीआई ऑटोपे
(घ) यूपीआई ग्लोबल
उत्तर: (ख)
व्याख्या: यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल — प्रत्यायोजित भुगतान) प्राथमिक उपयोगकर्ता को आश्रित द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को पूर्ण प्रत्यायोजन (₹15,000 मासिक व ₹5,000 प्रति लेन-देन सीमा) या आंशिक प्रत्यायोजन (प्रत्येक लेन-देन पर पिन अनुमोदन) देने की अनुमति देता है (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

24. **अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजनाओं, आईपीओ आवेदनों और कर भुगतान (कर) के लिए प्रति लेन-देन अधिकतम यूपीआई सीमा कितनी निर्धारित की गई है?**
(क) ₹1 लाख
(ख) ₹2 लाख
(ग) ₹5 लाख
(घ) ₹10 लाख
उत्तर: (ग)
व्याख्या: आरबीआई और एनपीसीआई ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, कर भुगतान, आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में यूपीआई की प्रति लेन-देन सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर **₹5 लाख** कर दिया है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

25. **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279क के अंतर्गत गठित 'जीएसटी परिषद' (जीएसटी) में किसी निर्णय को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत और केंद्र व राज्यों का मतदान भार क्या है?**
(क) साधारण बहुमत; केंद्र का भार 50% और राज्यों का भार 50%
(ख) दो-तिहाई बहुमत; केंद्र का भार 25% और राज्यों का भार 75%
(ग) तीन-चौथाई बहुमत; केंद्र सरकार के मत का भार 1/3 और सभी राज्यों के संयुक्त मतों का भार 2/3
(घ) सर्वसम्मति; प्रत्येक राज्य और केंद्र का एक समान मत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: अनुच्छेद 279क के अनुसार, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के **तीन-चौथाई** बहुमत से लिया जाता है, जिसमें केंद्र का मत भार **1/3** और सभी राज्यों का संयुक्त मत भार **2/3** होता है (**भारतीय संविधान**)।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

26. **हालिया जीएसटी परिषद बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार, जीएसटी अधिनियम की किस नई धारा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के गैर-धोखाधड़ी (धारा 73) कर मांग नोटिसों में मूल कर जमा करने पर ब्याज और जुर्माने को माफ किया गया है?**
(क) धारा 74
(ख) धारा 112
(ग) धारा 128क
(घ) धारा 171
उत्तर: (ग)
व्याख्या: जीएसटी परिषद की 53वीं व 54वीं बैठकों की सिफारिश पर जोड़ी गई **धारा 128क** के तहत शुरुआती तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2017–18, वित्त वर्ष19, वित्त वर्ष20) के धारा 73 के मामलों में निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने की 100% माफी दी गई है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

27. **अनावश्यक कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए क्रमशः कितनी न्यूनतम मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की हैं?**
(क) ₹10 लाख, ₹50 लाख और ₹1 करोड़
(ख) ₹20 लाख (जीएसटी), ₹1 करोड़ (उच्च न्यायालय) और ₹2 करोड़ (सर्वोच्च न्यायालय)
(ग) ₹50 लाख, ₹2 करोड़ और ₹5 करोड़
(घ) ₹5 लाख, ₹25 लाख और ₹50 लाख
उत्तर: (ख)
व्याख्या: जीएसटी परिषद ने सरकारी विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए **जीएसटी में ₹20 लाख, उच्च न्यायालय में ₹1 करोड़** और **सर्वोच्च न्यायालय में ₹2 करोड़** की मौद्रिक सीमा तय की है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

28. **वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी) की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है और इसके समक्ष अपील दायर करने के लिए विवादित कर राशि का पूर्व-जमा (पूर्व-जमा) घटाकर कितना कर दिया गया है?**
(क) मुंबई; 25 प्रतिशत
(ख) नई दिल्ली; 20% से घटाकर 10% (अधिकतम ₹20 करोड़ जीएसटी + ₹20 करोड़ जीएसटी)
(ग) कोलकाता; 15 प्रतिशत
(घ) चेन्नई; 5 प्रतिशत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: जीएसटी की प्रधान पीठ **नई दिल्ली** में स्थित है और करदाताओं की सुविधा के लिए इसके समक्ष अपील हेतु पूर्व-जमा (पूर्व-जमा) को 20% से घटाकर **10%** (अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ प्रत्येक) कर दिया गया है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

29. **सेबी (सेबी) के मार्च 2026 के मासिक बुलेटिन के अनुसार, फरवरी 2026 के अंत तक भारत में कुल डीमैट खातों की संख्या कितनी हो गई है (सीडीएसएल और एनएसडीएल को मिलाकर)?**
(क) 15.4 करोड़
(ख) 18.5 करोड़
(ग) 22.2 करोड़ (सीडीएसएल में 17.8 करोड़ और एनएसडीएल में 4.4 करोड़)
(घ) 25.8 करोड़
उत्तर: (ग)
व्याख्या: सेबी के मार्च 2026 के मासिक बुलेटिन के अनुसार, फरवरी 2026 के अंत में भारत में कुल डीमैट खातों की संख्या **22.2 करोड़** पर पहुँच गई, जिसमें **सीडीएसएल के पास 17.8 करोड़** और **एनएसडीएल के पास 4.4 करोड़** खाते हैं (**सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

30. **सेबी (सेबी) के मार्च 2026 के बुलेटिन के अनुसार, फरवरी 2026 के अंत में वार्षिक आधार (वार्षिक) पर कमोडिटी सूचकांक 'एमसीएक्स आईकॉमडेक्स ' ने कितने प्रतिशत का रिटर्न दर्ज किया, जिसका मुख्य चालक बुलियन सूचकांक में 101.5% की तेजी रही?**
(क) 24.5 प्रतिशत
(ख) 42.0 प्रतिशत
(ग) 69.1 प्रतिशत
(घ) 85.4 प्रतिशत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: सेबी बुलेटिन के अनुसार, फरवरी 2026 के अंत में वार्षिक आधार पर समग्र सूचकांक **एमसीएक्स आईकॉमडेक्स पर रिटर्न 69.1 प्रतिशत** रहा, जो मुख्य रूप से बुलियन सूचकांक में **101.5 प्रतिशत** की रैली और धातुओं में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित था (**सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

31. **सेबी के अगस्त 2026 के निपटान एवं जोखिम प्रबंधन परामर्श पत्र के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 12 महीनों से निष्क्रिय सदस्य को कितने रुपये से अधिक की अतिरिक्त 'बेस मिनिमम कैपिटल' (न्यूनतम आधार पूँजी) राशि शर्तों के अधीन वापस की जा सकती है?**
(क) ₹1 लाख से अधिक की अतिरिक्त न्यूनतम आधार पूँजी राशि
(ख) ₹10 लाख से अधिक की राशि
(ग) ₹50 लाख से अधिक की राशि
(घ) ₹1 करोड़ से अधिक की राशि
उत्तर: (क)
व्याख्या: सेबी के अगस्त 2026 के दस्तावेज के अनुसार, यदि किसी सदस्य ने पिछले 12 महीनों से कोई लेन-देन नहीं किया है, उसके विरुद्ध कोई निवेशक शिकायत या मध्यस्थता मामला लंबित नहीं है और उसने सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, तो **₹1 लाख से अधिक के अतिरिक्त न्यूनतम आधार पूँजी (न्यूनतम आधार पूँजी 1)** को वापस किया जा सकता है (**सेबी परामर्श पत्र — अगस्त 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

32. **भारतीय रिजर्व बैंक की 7 अक्टूबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा?**
(क) 645.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(ख) 689.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(ग) 704.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(घ) 734.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन)
उत्तर: (घ)
व्याख्या: आरबीआई की 7 अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, **2 अक्टूबर 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 734.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन)** पर खड़ा था (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

33. **आरबीआई की अक्टूबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान विश्व स्तर पर घोषित 'ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) परियोजनाओं में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ भारत का विश्व में कौन-सा स्थान रहा?**
(क) प्रथम स्थान
(ख) दूसरा स्थान
(ग) तीसरा स्थान
(घ) पाँचवाँ स्थान
उत्तर: (ग)
व्याख्या: आरबीआई के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान वैश्विक स्तर पर घोषित ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में भारत **41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 41.3 बिलियन)** के साथ **विश्व में तीसरे स्थान** पर रहा (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

34. **आरबीआई के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल–अगस्त के दौरान भारत में 'सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह' (सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह) में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई?**
(क) 10.2 प्रतिशत
(ख) 15.4 प्रतिशत
(ग) 20.6 प्रतिशत
(घ) 28.9 प्रतिशत
उत्तर: (ग)
व्याख्या: अप्रैल–अगस्त 2026–27 के दौरान भारत में **सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह) में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि** हुई, जबकि शुद्ध बहिर्गामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) बढ़कर 17.7 बिलियन हो गया (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

35. **अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान भारत को प्राप्त 'सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार' (बाह्य वाणिज्यिक उधार) बढ़कर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया?**
(क) 14.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(ख) 17.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
(ग) 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (शुद्ध अंतर्वाह अमेरिकी डॉलर 7.3 बिलियन)
(घ) 35.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर
उत्तर: (ग)
व्याख्या: अप्रैल–अगस्त 2026 के दौरान भारत को सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार) का संवितरण पिछले वर्ष के 17.0 बिलियन से बढ़कर **23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया, और पुनर्भुगतान समायोजित करने के बाद शुद्ध अंतर्वाह **7.3 बिलियन** रहा (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

36. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जुलाई 2026 के 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डब्ल्यूईओ, 2026) के अनुसार, विश्व वस्तु और सेवा व्यापार की मात्रा वृद्धि वर्ष 2025 के 5.0 प्रतिशत से वर्ष 2026 में कितनी रहने का अनुमान है?**
(क) 2.1 प्रतिशत
(ख) 3.5 प्रतिशत
(ग) 4.8 प्रतिशत
(घ) 6.2 प्रतिशत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डब्ल्यूईओ (जुलाई 2026) के अनुसार, विश्व वस्तु और सेवा व्यापार मात्रा वृद्धि वर्ष 2025 के 5.0 प्रतिशत से नरम होकर वर्ष 2026 में **3.5 प्रतिशत** रहने का अनुमान है (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

37. **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (अनुसूचित जाति) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण' (— प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) का कुल लक्ष्य (के प्रतिशत के रूप में) क्रमशः कितना है?**
(क) 30% और 50%
(ख) 40% और 75%
(ग) 45% और 60%
(घ) 50% और 80%
उत्तर: (ख)
व्याख्या: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (और 20+ शाखाओं वाले विदेशी बैंकों) के लिए कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य उनके का **40 प्रतिशत** है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) और लघु वित्त बैंकों (लघु वित्त बैंकों) के लिए यह लक्ष्य **75 प्रतिशत** है (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

38. **आरबीआई के आर्थिक पूँजी ढाँचे (रूपरेखा —) की समीक्षा करने वाली किस समिति ने सिफारिश की थी कि आरबीआई को अपनी बैलेंस शीट के 5.5% से 6.5% के बीच 'आकस्मिक जोखिम बफर' बनाए रखना चाहिए?**
(क) उर्जित पटेल समिति
(ख) बिमल जालान समिति (2018–19)
(ग) पी.जे. नायक समिति
(घ) नचिकेत मोर समिति
उत्तर: (ख)
व्याख्या: पूर्व आरबीआई गवर्नर **डॉ. बिमल जालान** की अध्यक्षता वाली समिति ने आकस्मिक जोखिम बफर को आरबीआई की बैलेंस शीट के आकार के **5.5% से 6.5%** के दायरे में रखने और शेष अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

39. **बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल बैंक खातों' की पहचान के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआई, बेंगलुरु) द्वारा विकसित इन-हाउस कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मॉडल का नाम क्या है?**
(क) फ्रॉड-शील्ड 2.0
(ख) म्यूलहंटर.एआई (म्यूलहंटर-एआई)
(ग) कवच-बैंक एआई
(घ) साइबर-प्रहरी
उत्तर: (ख)
व्याख्या: रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआई) ने म्यूल खातों का तेजी से पता लगाने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए **'म्यूलहंटर.एआई' (म्यूलहंटर-एआई)** नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित किया है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

40. **भारत में किन तीन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक' (— डी-एसआईबी / विफल होने के लिए अत्यंत विशाल) की सूची में रखा गया है?**
(क) एसबीआई (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बैंक ऑफ बड़ौदा)
(ख) एसबीआई (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक (एचडीएफसी बैंक) और आईसीआईसीआई बैंक (केंद्रीय सूचना आयोग)
(ग) एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक
(घ) एसबीआई, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
उत्तर: (ख)
व्याख्या: आरबीआई ने **भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक (एचडीएफसी बैंक) और आईसीआईसीआई बैंक (केंद्रीय सूचना आयोग)** को डी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्हें अपने बकेट के अनुसार अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूँजी बफर रखना होता है (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

41. **5 से 7 अक्टूबर 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित 63वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो दर के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?**
(क) 25 आधार अंकों की कटौती कर 5.00% किया गया
(ख) 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया
(ग) 25 आधार अंकों की वृद्धि कर 5.25% से बढ़ाकर 5.50% किया गया (स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और बैंक दर 5.75%)
(घ) 50 आधार अंकों की वृद्धि कर 5.75% किया गया
उत्तर: (ग)
व्याख्या: 63वीं मौद्रिक नीति समिति बैठक (5–7 अक्टूबर 2026) में गवर्नर **संजय मल्होत्रा** की अध्यक्षता में नीतिगत **रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.25% से 5.50%** किया गया, जिससे **स्थायी जमा सुविधा दर 5.25%** और **सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75%** हो गई (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

42. **16वें वित्त आयोग ने अपनी पाँच-वर्षीय पंचाट अवधि 2026–31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन कोष हेतु कुल कितने सहायता अनुदान की सिफारिश की है?**
(क) ₹5.50 लाख करोड़
(ख) ₹7.25 लाख करोड़
(ग) ₹9.47 लाख करोड़ (ग्रामीण निकाय ₹4.35 लाख करोड़ + शहरी निकाय ₹3.56 लाख करोड़ + आपदा प्रबंधन ₹1.56 लाख करोड़)
(घ) ₹12.20 लाख करोड़
उत्तर: (ग)
व्याख्या: 16वें वित्त आयोग ने 2026–31 के लिए कुल **₹9.47 लाख करोड़ के अनुदान** की सिफारिश की है (ग्रामीण स्थानीय निकाय ₹4.35 लाख करोड़, शहरी स्थानीय निकाय ₹3.56 लाख करोड़ और आपदा प्रबंधन ₹1.56 लाख करोड़) तथा राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त कर दिया है (**केंद्रीय बजट**)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

43. **8 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी के तहत आपराधिक अभियोजन चलाने की न्यूनतम कर-चोरी सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर कितना करने की सिफारिश की गई?**
(क) ₹2 करोड़
(ख) ₹3 करोड़
(ग) ₹5 करोड़ (तथा अधिकतम सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹10,000)
(घ) ₹10 करोड़
उत्तर: (ग)
व्याख्या: **57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026)** में अभियोजन की न्यूनतम सीमा को **₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़** करने और अधिकतम सामान्य जुर्माने को **₹25,000 से घटाकर ₹10,000** करने की सिफारिश की गई (पत्र सूचना कार्यालय)।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

44. **जनवरी 2026 में संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा?**
(क) वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% और नवाचार सूचकांक में 48वाँ स्थान
(ख) वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% (जीवीए 7.3%) और नवाचार सूचकांक में 38वाँ स्थान
(ग) वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% और नवाचार सूचकांक में 25वाँ स्थान
(घ) वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0% और नवाचार सूचकांक में 52वाँ स्थान
उत्तर: (ख)
व्याख्या: **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26** के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में **वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4%** (जीवीए 7.3%) रही, वित्त वर्ष 2026–27 के लिए **6.8%–7.2%** का अनुमान लगाया गया, और **वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान** पर पहुँचा (आर्थिक सर्वेक्षण)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

45. **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिनके नेतृत्व में वर्ष 2026 में दीर्घकालिक इक्विटी व्युत्पन्न अनुबंधों (लीप्स) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अनुपालन सरलीकरण के सुधार किए गए?**
(क) तुहिन कांत पांडे
(ख) अजय त्यागी
(ग) के.वी. कामथ
(घ) देबाशीष पांडा
उत्तर: (क)
व्याख्या: पूर्व वित्त एवं राजस्व सचिव **तुहिन कांत पांडे** सेबी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वर्ष 2026 में **दीर्घकालिक इक्विटी व्युत्पन्न अनुबंधों** और निवेशक संरक्षण सुधारों का नेतृत्व किया (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)।

त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 त्वरित पुनरावलोकन बिंदु — द्वितीय खंड)

1. **केंद्रीय बजट 2026–27 में कुल व्यय (बजट अनुमान 2026–27): ₹53.47 लाख करोड़** (जीडीपी का 13.6 प्रतिशत; संशोधित अनुमान 2025–26 के ₹49.65 लाख करोड़ पर 7.7% वृद्धि) (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (1): **केंद्रीय बजट 2026–27 में कुल व्यय (बजट अनुमान 2026–27)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

2. **संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 एवं बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राजकोषीय घाटा:** संशोधित अनुमान 2025–26 में जीडीपी का **4.4%** और बजट अनुमान 2026–27 में जीडीपी का **4.3%** (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (2): **संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26 एवं बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राजकोषीय घाटा** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

3. **केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी):** संशोधित अनुमान 2025–26 में **56.1%** से घटकर बजट अनुमान 2026–27 में **55.6%** अनुमानित (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (3): **केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात (--जीडीपी)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

4. **वर्ष 2030–31 के लिए केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात लक्ष्य:** जीडीपी का **50± 1 प्रतिशत** (केंद्रीय बजट भाषण 2026–27)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (4): **वर्ष 2030–31 के लिए केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात लक्ष्य** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

5. **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ): ₹35.33 लाख करोड़** (संशोधित अनुमान 2025–26 पर 5.7% वृद्धि) (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (5): **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

6. **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (कर): ₹28.67 लाख करोड़** (संशोधित अनुमान 2025–26 में ₹26.7 लाख करोड़ था) (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (6): **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (कर)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

7. **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में गैर-कर राजस्व (-कर) और ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ:** गैर-कर राजस्व **₹6.66 लाख करोड़** और ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ **₹1.18 लाख करोड़** (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (7): **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में गैर-कर राजस्व (-कर) और ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

8. **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में सकल अप्रत्यक्ष कर अनुमान: ₹17.07 लाख करोड़** (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (8): **बजट 2026–27 (बजट अनुमान) में सकल अप्रत्यक्ष कर अनुमान** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

9. **बजट 2026–27 में राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति) परिव्यय:** 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में **₹2.0 लाख करोड़** (केंद्रीय कैपेक्स जीडीपी का 3.1%) (राजकोषीय नीति विवरण)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (9): **बजट 2026–27 में राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति) परिव्यय** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

10. **16वें वित्त आयोग की प्रथम वर्ष (2026–27) की स्वीकृत सिफारिशें:** विभाज्य कर पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी **41%** पर बरकरार; वित्त वर्ष 2026–27 में राज्यों को **₹1.4 लाख करोड़** का वित्त आयोग अनुदान (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (10): **16वें वित्त आयोग की प्रथम वर्ष (2026–27) की स्वीकृत सिफारिशें** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

11. **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) का वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान: 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत** (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (11): **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) का वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

12. **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय/जीडीपी):** महामारी-पूर्व के 2.7% औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 में जीडीपी का **4 प्रतिशत** (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (12): **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय/जीडीपी)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

13. **राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय/जीडीपी):** केंद्र की अनुसूचित जाति योजना से प्रोत्साहित होकर जीडीपी के **2.4 प्रतिशत** पर कायम (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (13): **राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय/जीडीपी)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

14. **संघीय राजकोषीय घाटे की 5-वर्षीय कटौती यात्रा:** वित्त वर्ष 2020–21 के **9.2%** (तथा वित्त वर्ष 2021–22 के 6.7%) से घटकर आधे से भी कम — वित्त वर्ष 2026 संकलन–25 में **4.8%**, संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2025–26 में **4.4%** और बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27 में **4.3%** (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (14): **संघीय राजकोषीय घाटे की 5-वर्षीय कटौती यात्रा** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

15. **बजट 2026–27 में शेयर बायबैक (अंश पुनर्खरीद) कराधान सुधार:** सभी शेयरधारकों के लिए **'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ)** के रूप में कर योग्य; प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) पर अतिरिक्त बायबैक कर (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (15): **बजट 2026–27 में शेयर बायबैक (अंश पुनर्खरीद) कराधान सुधार** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

16. **न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) सुधार (बजट 2026–27):** न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर बनाने का प्रस्ताव और नई कर व्यवस्था में कर देयता के **1/4 (एक-चौथाई)** तक उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट सेट-ऑफ की अनुमति (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (16): **न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) सुधार (बजट 2026–27)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

17. **बजट 2026–27 में कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क छूट:** कैंसर रोगियों के लिए **17 जीवनरक्षक दवाओं/औषधियों** पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क) से पूर्ण छूट (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (17): **बजट 2026–27 में कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क छूट** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

18. **कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) का रोलआउट:** कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल डिजिटल विंडो के साथ **2 वर्षों में** सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली लागू करने की घोषणा (केंद्रीय बजट के मुख्य बिंदु)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (18): **कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) का रोलआउट** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

19. **एंजेल टैक्स (धारा 56(सात-ख)) एवं विदेशी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स:** स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स पूर्णतः समाप्त; विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर 40% से घटाकर **35%** किया गया (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (19): **एंजेल टैक्स (धारा 56(सात-ख)) एवं विदेशी कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

20. **सोने, चाँदी एवं प्लैटिनम पर सीमा शुल्क युक्तिकरण:** सोने और चाँदी पर सीमा शुल्क घटाकर **6%** और प्लैटिनम पर **6.4%** किया गया तथा 25 महत्वपूर्ण खनिजों (महत्वपूर्ण खनिजों) पर मूल सीमा शुल्क मुक्त (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (20): **सोने, चाँदी एवं प्लैटिनम पर सीमा शुल्क युक्तिकरण** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

21. **आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा जून 2025 में सीआरआर कटौती की घोषणा:** बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में चरणबद्ध रूप से **100 आधार अंकों (100 आधार अंक)** की कटौती (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (21): **आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा जून 2025 में सीआरआर कटौती की घोषणा** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

22. **अक्टूबर 2026 की आरबीआई मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर: 5.75 प्रतिशत** (आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (22): **अक्टूबर 2026 की आरबीआई मौद्रिक नीति में सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

23. **मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति — धारा 45यख, आरबीआई अधिनियम 1934):** कुल **6 सदस्य** (3 आरबीआई आंतरिक + 3 केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष हेतु नामित बाह्य सदस्य); मुद्रास्फीति लक्ष्य **4% ± 2% (2% से 6%)** (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (23): **मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति — धारा 45यख, आरबीआई अधिनियम 1934)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

24. **स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा — अप्रैल 2022 में शुरू):** तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर का नया फ्लोर (निचली सीमा); आरबीआई द्वारा **बिना किसी सरकारी प्रतिभूति संपार्श्विक** के तरलता अवशोषण (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (24): **स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा — अप्रैल 2022 में शुरू)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

25. **जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट (जून 2025):** बिना बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के **50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 50 मिलियन)** तक अग्रिम भुगतान की अनुमति (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (25): **जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट (जून 2025)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

26. **आरबीआई (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025:** 16 जून 2025 को जारी; 2018 के निदेशों की समीक्षा के बाद वित्तीय बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच संचालकों हेतु नया नियामक ढाँचा (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (26): **आरबीआई (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

27. **बैंकों के लिए परिपक्वता तक धारित सीमा का पुनर्स्थापन:** महामारी काल की 23% सीमा से चरणबद्ध रूप से घटाकर शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ के **19.5 प्रतिशत** पर बहाल (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (27): **बैंकों के लिए परिपक्वता तक धारित सीमा का पुनर्स्थापन** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

28. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए संशोधित इंटरनेट बैंकिंग पात्रता मानदंड:** न्यूनतम नेटवर्थ **₹50 करोड़**, न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात **9%**, अधिकतम शुद्ध एनपीए **5% से अनधिक** और ठीक **पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ** (आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (28): **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के लिए संशोधित इंटरनेट बैंकिंग पात्रता मानदंड** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

29. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) की शेयर पूँजी संरचना: केंद्र सरकार : प्रायोजक बैंक : संबंधित राज्य सरकार** (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (29): **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) की शेयर पूँजी संरचना** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

30. **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) के अनिवार्य लक्ष्य:** वाणिज्यिक बैंक — **40%** (कृषि 18%, लघु-सीमांत किसान 10%, सूक्ष्म इकाइयाँ 7.5%, कमजोर वर्ग 12%); क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों — **75%**; शहरी सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों) — **60%** (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (30): **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) के अनिवार्य लक्ष्य** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

31. **बेसल- मानकों के तहत भारत में न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी पर्याप्तता अनुपात): 9 प्रतिशत** (तथा 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर सहित कुल **11.5 प्रतिशत**) (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (31): **बेसल- मानकों के तहत भारत में न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी पर्याप्तता अनुपात)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

32. **भारत के तीन घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक (एचडीएफसी बैंक) और आईसीआईसीआई बैंक (केंद्रीय सूचना आयोग)** (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (32): **भारत के तीन घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

33. **आरबीआई के प्रमुख नागरिक व नियामक पोर्टल: उद्गम (उद्गम)** — लावारिस जमा खोज पोर्टल; **प्रवाह (प्रवाह)** — ऑनलाइन विनियामक अनुमोदन पोर्टल; **दक्ष (दक्ष)** — पर्यवेक्षी सुपरटेक पोर्टल (भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (33): **आरबीआई के प्रमुख नागरिक व नियामक पोर्टल** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

34. **म्यूलहंटर.एआई (म्यूलहंटर-एआई):** रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआई, बेंगलुरु) द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खातों को पकड़ने हेतु विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (34): **म्यूलहंटर.एआई (म्यूलहंटर-एआई)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

35. **भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना विस्तार: पीएम विश्वकर्मा योजना** के लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर डिजिटल लेन-देन हेतु पीआईडीएफ में शामिल किया गया (**आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (35): **भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना विस्तार** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

36. **एनपीसीआई का 'यूपीआई लाइट' (यूपीआई लाइट): ₹1,000 से कम (₹1,000)** के लेन-देन हेतु पिन-रहित ऑन-डिवाइस वॉलेट; कुल वॉलेट सीमा **₹5,000** (ई-मैंडेट ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा सहित) (**एनपीसीआई — यूपीआई लाइट**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (36): **एनपीसीआई का 'यूपीआई लाइट' (यूपीआई लाइट)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम**)।

37. **यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल — प्रत्यायोजित भुगतान):** प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/आश्रितों को भुगतान अधिकार सौंपने की सुविधा (पूर्ण प्रत्यायोजन में **₹15,000 मासिक** व **₹5,000 प्रति लेन-देन** सीमा) (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (37): **यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल — प्रत्यायोजित भुगतान)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम**)।

38. *यूपीआई व्यापार सक्षम योजना (यूपीआई परिचालन परिपत्र 242, वित्त वर्ष 26–27):* छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) के बीच यूपीआई भुगतान स्वीकार्यता को बढ़ावा देने हेतु एनपीसीआई की योजना (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

39. *माई-यूपीआई ("यूपीआई" / यूपीआई सहायता 2.0 — परिचालन परिपत्र 227, वित्त वर्ष 26–27):* यूपीआई भुगतानों और शिकायतों के समाधान हेतु एनपीसीआई की कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित ग्राहक सहायता प्रणाली (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

40. *पीओएस पर यूपीआई टैप एंड पे (यूपीआई परिचालन परिपत्र 186, वित्त वर्ष 26–27):* प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों पर एनएफसी (एनएफसी) तकनीक से संपर्क-रहित टैप भुगतान (**एनपीसीआई यूपीआई परिपत्र**)।

41. **यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे):** बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन उपयोगकर्ताओं हेतु यूपीआई सुविधा; प्रति लेन-देन सीमा बढ़ाकर **₹10,000** की गई (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (41): **यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

42. **उच्च-मूल्य यूपीआई लेन-देन सीमा (₹5 लाख):** अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, कर भुगतान (कर), आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजनाओं हेतु प्रति लेन-देन सीमा **₹5 लाख** (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (42): **उच्च-मूल्य यूपीआई लेन-देन सीमा (₹5 लाख)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

43. **डिजिटल रुपया (सीबीडीसी / ई-रुपया):** आरबीआई द्वारा जारी वैध डिजिटल मुद्रा — दो रूप: **खुदरा (ई-रुपया खुदरा)** और **थोक (ई-रुपया थोक)** (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (43): **डिजिटल रुपया (सीबीडीसी / ई-रुपया)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

44. **जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क — 101वाँ संविधान संशोधन, 2016):** अध्यक्ष — केंद्रीय वित्त मंत्री; गणपूर्ति — 50%; निर्णय हेतु आवश्यक भारित बहुमत — 75% **(केंद्र का मत भार 1/3 + राज्यों का मत भार 2/3)** (**भारतीय संविधान**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (44): **जीएसटी परिषद (अनुच्छेद 279क — 101वाँ संविधान संशोधन, 2016)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय संविधान**)।

45. **जीएसटी अधिनियम की नई धारा 128क (जीएसटी एमनेस्टी स्कीम):** वित्त वर्ष **2017–18, 2018–19 और 2019–20** के गैर-धोखाधड़ी (धारा 73) कर नोटिसों में मूल कर चुकाने पर ब्याज और जुर्माने की पूर्ण माफी (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (45): **जीएसटी अधिनियम की नई धारा 128क (जीएसटी एमनेस्टी स्कीम)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

46. **जीएसटी में विभागीय अपील की न्यूनतम मौद्रिक सीमाएँ: जीएसटी: ₹20 लाख; उच्च न्यायालय: ₹1 करोड़**; और **सर्वोच्च न्यायालय: ₹2 करोड़** (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (46): **जीएसटी में विभागीय अपील की न्यूनतम मौद्रिक सीमाएँ** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

47. **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी):** प्रधान पीठ **नई दिल्ली** में; अपील हेतु पूर्व-जमा (पूर्व-जमा) 20% से घटाकर **10%** (अधिकतम ₹20 करोड़ जीएसटी + ₹20 करोड़ जीएसटी) किया गया (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (47): **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटी)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

48. **फर्जी चालान रोकने हेतु अखिल भारतीय जीएसटी सुधार:** नए जीएसटी पंजीकरण आवेदकों के लिए पूरे देश में **बायोमेसूत्र-आधारित आधार प्रमाणीकरण** और फॉर्म **जीएसटी-1** की शुरुआत (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (48): **फर्जी चालान रोकने हेतु अखिल भारतीय जीएसटी सुधार** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

49. **भारत में कुल डीमैट खाते (फरवरी 2026 के अंत में — सेबी बुलेटिन):** कुल **22.2 करोड़ खाते** (**सीडीएसएल में 17.8 करोड़** और **एनएसडीएल में 4.4 करोड़**) (**सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (49): **भारत में कुल डीमैट खाते (फरवरी 2026 के अंत में — सेबी बुलेटिन)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

50. **एमसीएक्स आईकॉमडेक्स समग्र कमोडिटी सूचकांक रिटर्न (फरवरी 2026 वार्षिक): 69.1 प्रतिशत** की वार्षिक वृद्धि (बुलियन सूचकांक में **101.5%** की ऐतिहासिक तेजी से प्रेरित) (**सेबी मासिक बुलेटिन — मार्च 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (50): **एमसीएक्स आईकॉमडेक्स समग्र कमोडिटी सूचकांक रिटर्न (फरवरी 2026 वार्षिक)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

51. **सेबी का टी+0 निपटान चक्र एवं म्यूचुअल फंड नेट सेटलमेंट:** टी+1 के बाद चुनिंदा शेयरों में **उसी दिन (टी+0) निपटान** लागू तथा कैश सेगमेंट में म्यूचुअल फंड योजनाओं हेतु शुद्ध निपटान (शुद्ध निपटान) फ्रेमवर्क (**सेबी परिपत्र पोर्टल**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (51): **सेबी का टी+0 निपटान चक्र एवं म्यूचुअल फंड नेट सेटलमेंट** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

52. **सेबी का नया एसेट क्लास एवं वायदा एवं विकल्प कॉन्ट्रैक्ट साइज:** उच्च जोखिम निवेशकों हेतु न्यूनतम **₹10 लाख** निवेश वाला नया एसेट क्लास; इक्विटी वायदा एवं विकल्प में न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट आकार बढ़ाकर **₹15 लाख** किया गया (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (52): **सेबी का नया एसेट क्लास एवं वायदा एवं विकल्प कॉन्ट्रैक्ट साइज** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

53. **निष्क्रिय स्टॉक एक्सचेंज सदस्यों को न्यूनतम आधार पूँजी रिफंड (सेबी अगस्त 2026):** 12 महीने से निष्क्रिय सदस्यों को सेबी अनापत्ति प्रमाणपत्र और शिकायत-मुक्त होने पर **₹1 लाख से अधिक के अतिरिक्त बेस मिनिमम कैपिटल (न्यूनतम आधार पूँजी)** की वापसी (**सेबी परामर्श पत्र — अगस्त 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (53): **निष्क्रिय स्टॉक एक्सचेंज सदस्यों को न्यूनतम आधार पूँजी रिफंड (सेबी अगस्त 2026)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

54. **भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार (2 अक्टूबर 2026 को — आरबीआई): 734.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 734.6 बिलियन)** (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (54): **भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार (2 अक्टूबर 2026 को — आरबीआई)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

55. **विदेशी मुद्रा भंडार के 4 आधिकारिक घटक:** विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (विदेशी मुद्रा आस्तियाँ), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (विशेष आहरण अधिकार), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (रिजर्व ट्रेंच पोजीशन) (**भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (55): **विदेशी मुद्रा भंडार के 4 आधिकारिक घटक** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

56. **अप्रैल–अगस्त 2026–27 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि:** भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह) में **20.6 प्रतिशत** की वृद्धि; शुद्ध बहिर्गामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **17.7 बिलियन** (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (56): **अप्रैल–अगस्त 2026–27 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

57. **वैश्विक ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में भारत की रैंक (अप्रैल–अगस्त 2026): 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अमेरिकी डॉलर 41.3 बिलियन)** के साथ भारत **विश्व में तीसरे स्थान** पर (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (57): **वैश्विक ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं में भारत की रैंक (अप्रैल–अगस्त 2026)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

58. **अप्रैल–अगस्त 2026 में बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार):** सकल बाह्य वाणिज्यिक उधार संवितरण बढ़कर **23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर** (तथा शुद्ध अंतर्वाह **7.3 बिलियन**) रहा (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (58): **अप्रैल–अगस्त 2026 में बाह्य वाणिज्यिक उधार (बाह्य वाणिज्यिक उधार)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

59. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (जुलाई 2026) व्यापार वृद्धि अनुमान:** विश्व वस्तु और सेवा व्यापार मात्रा वृद्धि वर्ष 2025 के 5.0% से वर्ष 2026 में **3.5 प्रतिशत** रहने का अनुमान (**आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (59): **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (जुलाई 2026) व्यापार वृद्धि अनुमान** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

. **63वीं आरबीआई मौद्रिक नीति समिति बैठक (5–7 अक्टूबर 2026):** गवर्नर **संजय मल्होत्रा** की अध्यक्षता में **रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50%** की गई (स्थायी जमा सुविधा दर **5.25%**, बैंक दर **5.75%**) (**भारतीय रिजर्व बैंक**)।

62. **16वें वित्त आयोग का पाँच-वर्षीय अनुदान (2026–31):** कुल **₹9.47 लाख करोड़** (ग्रामीण निकाय **₹4.35 लाख करोड़**, शहरी निकाय **₹3.56 लाख करोड़**, आपदा प्रबंधन **₹1.56 लाख करोड़**; राजस्व घाटा अनुदान समाप्त) (**केंद्रीय बजट**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (62): **16वें वित्त आयोग का पाँच-वर्षीय अनुदान (2026–31)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**केंद्रीय बजट पोर्टल**)।

63. **57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026):** आपराधिक अभियोजन की सीमा **₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़** और अधिकतम सामान्य दंड **₹25,000 से घटाकर ₹10,000** किया गया (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (63): **57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**पत्र सूचना कार्यालय**)।

64. **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के प्रमुख निष्कर्ष:** वित्त वर्ष 2025–26 में **वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4%** (जीवीए 7.3%), संभावित वृद्धि ~7%, **वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वाँ स्थान**, और बैंक एनपीए वसूली दर दोगुनी होकर **26.2%** (**आर्थिक सर्वेक्षण**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (64): **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के प्रमुख निष्कर्ष** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**केंद्रीय बजट पोर्टल**)।

65. **सेबी के 2026 सुधार (अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे):** संस्थागत हेजिंग हेतु **दीर्घकालिक इक्विटी व्युत्पन्न अनुबंधों** को प्रोत्साहन, वैकल्पिक **टी+0 निपटान** और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पंजीकरण का सरलीकरण (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (65): **सेबी के 2026 सुधार (अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

8.6 परीक्षा-उन्मुख समेकित संदर्भ सारणी: प्रमुख आर्थिक एवं राजव्यवस्था योजनाएँ, आयोग एवं वैश्विक वित्तीय संस्थान (2026 संकलन)

योजना / आयोग / वैश्विक संस्था	स्थापना / प्रारंभ वर्ष एवं मुख्यालय	प्रमुख संवैधानिक / आर्थिक प्रावधान एवं 2025–26 नवीनतम विवरण	लक्षित क्षेत्र एवं परीक्षा-उपयोगी मुख्य बिंदु	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
पीएम विश्वकर्मा योजना (प्रधानमंत्री)	17 सितंबर 2023 (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)	₹13,000 करोड़ परिव्यय; 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों को बिना गारंटी ₹3 लाख तक ऋण (₹1 लाख + ₹2 लाख, 5% रियायती ब्याज पर)	आरबीआई ने **पीआईडीएफ योजना** में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को भी डिजिटल भुगतान उपकरणों हेतु शामिल किया	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	2026 संकलन (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	₹75,021 करोड़ परिव्यय; 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा (छत सौर ऊर्जा) से प्रतिमाह **300 यूनिट तक मुफ्त बिजली**	1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या अधिक पर **₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (प्रधानमंत्री-)	15 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस — जनजातीय कार्य मंत्रालय)	₹24,104 करोड़ परिव्यय; 18 राज्यों व 1 केंद्रशासित प्रदेश के 75 **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों)** का संतृप्तिकरण	9 मंत्रालयों के माध्यम से पक्के आवास, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)	2026 संकलन (बजट 2024–25 घोषणा)	₹79,156 करोड़ परिव्यय; 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों का समग्र विकास	17 केंद्रीय मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेपों द्वारा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में शत-प्रतिशत कवरेज	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
एकीकृत पेंशन योजना (एकीकृत पेंशन योजना — यूपीएस)	2026 संकलन स्वीकृत (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी)	25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पर सेवानिवृत्ति से पूर्व के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का **50% सुनिश्चित पेंशन**	10 वर्ष की सेवा पर **₹10,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन**; पारिवारिक पेंशन 60%; सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर **18.5%**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)	1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन); मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.	191 सदस्य देश (190वाँ अंडोरा, 191वाँ लिकटेंस्टीन); प्रमुख रिपोर्ट: **विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ)** एवं **वैश्विक वित्तीय स्थिरता प्रतिवेदन (जीएफएसआर)**	डब्ल्यूईओ (जुलाई 2026) के अनुसार विश्व वस्तु एवं सेवा व्यापार वृद्धि 2025 के 5.0% से 2026 में **3.5%** अनुमानित	आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति — अक्टूबर 2026
विश्व बैंक समूह (विश्व बैंक समूह — आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी)	1944 (ब्रेटन वुड्स); मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.	प्रमुख रिपोर्ट: **विश्व विकास प्रतिवेदन, वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ, लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई)** एवं **-संशोधित अनुमान**	भारत आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी और मीगा का सदस्य है, किंतु **आईसीएसआईडी (निवेश विवाद निपटान केंद्र) का सदस्य नहीं** है	केंद्रीय बजट पोर्टल
न्यू डेवलपमेंट बैंक (न्यू डेवलपमेंट बैंक) एवं एआईआईबी (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)	न्यू डेवलपमेंट बैंक: 2014 (फोर्टालेजा घोषणा — मुख्यालय: शंघाई) \	कृत्रिम बुद्धिमत्ता: 2016 (मुख्यालय: बीजिंग)	ब्रिक्स (ब्रिक्स) देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी संस्थापक सदस्यों का समान मताधिकार; भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक	सतत बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी परिवहन परियोजनाओं का वित्तपोषण	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

• अंतिम पुनरीक्षण सूत्र — भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों एवं आर्थिक विषयों का समन्वय:

1. **प्रथम अनुसूची (अनुच्छेद 1 एवं 4):** 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र (भारतीय संविधान)।

2. **द्वितीय अनुसूची:** राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति/उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सीएजी के वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार (भारतीय संविधान)।

3. **तृतीय अनुसूची:** संघ व राज्य के मंत्रियों, संसद व विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवारों, सांसदों/विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों और सीएजी द्वारा ली जाने वाली **शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ या प्रतिज्ञान)** के प्रारूप (राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 की शपथ संबंधित अनुच्छेदों में ही दी गई है) (भारतीय संविधान)।

4. **चतुर्थ अनुसूची (अनुच्छेद 4 एवं 80):** राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के लिए **राज्यसभा में सीटों का आवंटन** (भारतीय संविधान)।

5. **पंचम एवं षष्ठ अनुसूची (अनुच्छेद 244):** 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन (जनजातीय सलाहकार परिषद — जनजातीय सलाहकार परिषद: अधिकतम 20 सदस्य, जिनमें 3/4 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति विधायक); 6वीं अनुसूची में **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (सूत्र: असम-मेघालय-त्रिपुरा-मिजोरम)** के जनजातीय क्षेत्रों का स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा प्रशासन (भारतीय संविधान)।

6. **सप्तम अनुसूची (अनुच्छेद 246):** संघ सूची (100 विषय — प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, जनगणना, शेयर बाजार, निगम कर), राज्य सूची (61 विषय — लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, भूमि व खनिज अधिकार कर प्रविष्टि 49-50, नशीली व औद्योगिक मदिरा प्रविष्टि 8) और समवर्ती सूची (52 विषय — आपराधिक कानून बीएनएस/बीएनएस, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन) (भारतीय संविधान)।

7. **अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद 344 एवं 351):** संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त **22 भाषाएँ** (मूल रूप से 14 भाषाएँ; 21वें संशोधन 1967 से सिंधी, 71वें संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली; साथ ही शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया के बाद 2026 संकलन में **मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली** को जोड़कर कुल **11 शास्त्रीय भाषाएँ** घोषित की गईं) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

8. **नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश अनुसूची: 9वीं अनुसूची** (प्रथम संशोधन 1951 — भूमि सुधार; आई.आर. कोएल्हो वाद 2007 के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल कानून न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन); **10वीं अनुसूची** (52वाँ संशोधन 1985 — दलबदल विरोधी कानून; 91वें संशोधन 2003 से 1/3 विभाजन का अपवाद समाप्त कर केवल 2/3 विलय मान्य); **11वीं अनुसूची** (73वाँ संशोधन 1992 — पंचायतों के 29 विषय, अनुच्छेद 243छ); और **12वीं अनुसूची** (74वाँ संशोधन 1992 — नगरपालिकाओं के 18 विषय, अनुच्छेद 243ब) (भारतीय संविधान)।

व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
1	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	कुल व्यय	₹49.65 लाख करोड़ (~₹49.6 लाख करोड़) — ₹53.47 लाख करोड़ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
2	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)	₹33.42 लाख करोड़ (आधार) — ₹35.33 लाख करोड़ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
3	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	शुद्ध कर राजस्व (कर)	₹26.7 लाख करोड़ — ₹28.67 लाख करोड़ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
4	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति)	राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम — ₹2.0 लाख करोड़ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
5	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी)	4.4% (जीडीपी का) — 4.3% (जीडीपी का) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
6	राजकोषीय संकेतक / बजट मद	केंद्र सरकार का कुल ऋण (-- जीडीपी)	56.1% (जीडीपी का) — 55.6% (जीडीपी का) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
7	वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27)	वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव — 6.8% से 7.2% (वित्त वर्ष 2026–27) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
8	वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी)	महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) — 4.0% (जीडीपी का — वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
9	वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी)	राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता — 2.4% (जीडीपी का) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
10	वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती	वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% — 4.8% (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) \ 4.4% (संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2025–26) \ 4.3% (बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
11	वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र	उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान	कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क — सीमा शुल्क युक्तिकरण द्वारा सुधार (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
12	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर)	घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान — सभी शेयरधारकों हेतु 'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ) के रूप में कराधान; प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) पर अतिरिक्त बायबैक कर (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
13	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ	नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध — न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर (कर) बनाने का प्रस्ताव; नई कर व्यवस्था में कर देयता के 1/4 तक न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट सेट-ऑफ की अनुमति (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
14	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क)	3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार — कैंसर रोगियों के लिए 17 जीवनरक्षक दवाओं/औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
15	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो	अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया — 2 वर्षों में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली का रोलआउट एवं कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
16	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान	15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी — 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी यथावत स्वीकार; वित्त वर्ष 2026–27 हेतु राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ का वित्त आयोग अनुदान (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
17	कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान	स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर	अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर — एंजेल टैक्स (धारा 56(सात-ख)) पूर्णतः समाप्त; विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटकर 35% (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
18	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख — 6 सदस्य (3 आरबीआई आंतरिक + 3 सरकार द्वारा नामित बाह्य सदस्य); गवर्नर के पास निर्णायक मत (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
19	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 — प्रत्येक बैंक को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित प्रतिशत केवल नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है (बैंकों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
20	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 — बैंकों को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित भाग स्वयं के पास नकद, स्वर्ण या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
21	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा)	आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 — तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की निचली सीमा; संपार्श्विक-मुक्त तरलता अवशोषण उपकरण (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
22	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर	आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) — तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की ऊपरी सीमा; एसएलआर कोटे में से ओवरनाइट आपात उधार (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
23	मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान	जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट	फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन — शिपिंग पोत के आयात हेतु बिना बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के अग्रिम विप्रेषण (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
24	नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत	₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) — ₹50 करोड़ या अधिक (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को) (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
25	नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त	पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ — ठीक पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
26	नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य	वाणिज्यिक बैंक: 40% \ — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/लघु वित्त बैंक: 75% \ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
27	नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष)	पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ — उद्गम: लावारिस जमा खोज पोर्टल \ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
28	नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल	भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ)	टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती — अवधि दिसंबर 2025 तक विस्तारित; पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी पीआईडीएफ में शामिल किया गया (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
29	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)	ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान — प्रति लेन-देन: ₹1,000 से कम (₹1,000) \ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
30	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)	प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन — पूर्ण प्रत्यायोजन में: ₹15,000 मासिक एवं ₹5,000 प्रति लेन-देन (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
31	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)	बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान — प्रति लेन-देन सीमा: ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की गई (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
32	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0)	एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान — 247 स्वचालित शिकायत निवारण और रीयल-टाइम ट्रैकिंग (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
33	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे	छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान — छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) और संपर्क-रहित पीओएस भुगतानों पर केंद्रित (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
34	डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा	मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ	2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर — सामान्य: ₹1 लाख \ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)
35	जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र	जीएसटी परिषद की मतदान संरचना	अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) — गणपूर्ति: 50% \ (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल)

बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (कुल व्यय):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में कुल व्यय का सही विवरण ₹49.65 लाख करोड़ (~₹49.6 लाख करोड़) है। **कथन-II (कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ) का सही विवरण ₹33.42 लाख करोड़ (आधार) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**कुल व्यय: ₹49.65 लाख करोड़ (~₹49.6 लाख करोड़)**) और कथन-II (**कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ): ₹33.42 लाख करोड़ (आधार)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (शुद्ध कर राजस्व (कर)):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में शुद्ध कर राजस्व (कर) का सही विवरण ₹26.7 लाख करोड़ है। **कथन-II (राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति)):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति) का सही विवरण राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**शुद्ध कर राजस्व (कर): ₹26.7 लाख करोड़**) और कथन-II (**राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति): राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी)):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी) का सही विवरण 4.4% (जीडीपी का) है। **कथन-II (केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी)):** राजकोषीय संकेतक / बजट मद के संदर्भ में केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी) का सही विवरण 56.1% (जीडीपी का) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी): 4.4% (जीडीपी का)**) और कथन-II (**केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी): 56.1% (जीडीपी का)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27)):** वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र के संदर्भ में वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27) का सही विवरण वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव है। **कथन-II (केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी)):** वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र के संदर्भ में केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी) का सही विवरण महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27): वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव**) और कथन-II (**केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी): महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी)):** वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र के संदर्भ में राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी) का सही विवरण राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता है। **कथन-II (संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती):** वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र के संदर्भ में संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती का सही विवरण वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी): राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता**) और कथन-II (**संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती: वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7%**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान):** वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र के संदर्भ में उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान का सही विवरण कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क है। **कथन-II (शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर)):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर) का सही विवरण घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान: कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क**) और कथन-II (**शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर): घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ का सही विवरण नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध है। **कथन-II (कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क)):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क) का सही विवरण 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ: नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध**) और कथन-II (**कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क): 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो का सही विवरण अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया है। **कथन-II (16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान का सही विवरण 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो: अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया**) और कथन-II (**16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान: 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर):** कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान के संदर्भ में स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर का सही विवरण अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर है। **कथन-II (मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति) का सही विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर: अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर**) और कथन-II (**मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति): आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का सही विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 है। **कथन-II (सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) का सही विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42**) और कथन-II (**सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर): बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा)):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा) का सही विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 है। **कथन-II (सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर का सही विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा): आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17**) और कथन-II (**सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट):** मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान के संदर्भ में जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट का सही विवरण फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन है। **कथन-II (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत):** नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत का सही विवरण ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट: फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन**) और कथन-II (**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत: ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त):** नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त का सही विवरण पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ है। **कथन-II (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य):** नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल के संदर्भ में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य का सही विवरण वाणिज्यिक बैंक: 40% \ है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त: पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ**) और कथन-II (**प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य: वाणिज्यिक बैंक: 40% **) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष)):** नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल के संदर्भ में उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष) का सही विवरण पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ है। **कथन-II (भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ)):** नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल के संदर्भ में भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) का सही विवरण टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष): पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ**) और कथन-II (**भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ): टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट) का सही विवरण ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान है। **कथन-II (यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल) का सही विवरण प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट): ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान**) और कथन-II (**यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल): प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे) का सही विवरण बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान है। **कथन-II (माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0)):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0) का सही विवरण एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे): बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान**) और कथन-II (**माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0): एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे का सही विवरण छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान है। **कथन-II (मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ):** डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा के संदर्भ में मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ का सही विवरण 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे: छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान**) और कथन-II (**मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ: 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (जीएसटी परिषद की मतदान संरचना):** जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र के संदर्भ में जीएसटी परिषद की मतदान संरचना का सही विवरण अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) है। **कथन-II (जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई 5 पेट्रोलियम वस्तुएँ):** जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र के संदर्भ में जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई 5 पेट्रोलियम वस्तुएँ का सही विवरण अनुच्छेद 279क एवं मानवीय उपभोग की शराब है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**जीएसटी परिषद की मतदान संरचना: अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)**) और कथन-II (**जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई 5 पेट्रोलियम वस्तुएँ: अनुच्छेद 279क एवं मानवीय उपभोग की शराब**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)।

अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'कुल व्यय'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ₹49.65 लाख करोड़ (~₹49.6 लाख करोड़) (B) ₹33.42 लाख करोड़ (आधार) (C) ₹26.7 लाख करोड़ (D) राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम **उत्तर: (A) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'कुल व्यय'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **₹49.65 लाख करोड़ (~₹49.6 लाख करोड़)** है। विशेष तथ्य: ₹53.47 लाख करोड़। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ₹26.7 लाख करोड़ (B) ₹33.42 लाख करोड़ (आधार) (C) राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम (D) 4.4% (जीडीपी का) **उत्तर: (B) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'कुल राजस्व प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ)'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **₹33.42 लाख करोड़ (आधार)** है। विशेष तथ्य: ₹35.33 लाख करोड़। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'शुद्ध कर राजस्व (कर)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम (B) 4.4% (जीडीपी का) (C) ₹26.7 लाख करोड़ (D) 56.1% (जीडीपी का) **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'शुद्ध कर राजस्व (कर)'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **₹26.7 लाख करोड़** है। विशेष तथ्य: ₹28.67 लाख करोड़। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 4.4% (जीडीपी का) (B) 56.1% (जीडीपी का) (C) वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव (D) राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम **उत्तर: (D) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता (अनुसूचित जाति)'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **राज्यों का कैपेक्स जीडीपी के 2.4% पर कायम** है। विशेष तथ्य: ₹2.0 लाख करोड़। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 4.4% (जीडीपी का) (B) 56.1% (जीडीपी का) (C) वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव (D) महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राजकोषीय घाटा (— % जीडीपी)'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **4.4% (जीडीपी का)** है। विशेष तथ्य: 4.3% (जीडीपी का)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. 'राजकोषीय संकेतक / बजट मद' एवं 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' के संदर्भ में, **'केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव (B) 56.1% (जीडीपी का) (C) महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) (D) राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'केंद्र सरकार का कुल ऋण (--जीडीपी)'** (राजकोषीय संकेतक / बजट मद) का सही 'संशोधित अनुमान (संशोधित अनुमान) 2025–26' **56.1% (जीडीपी का)** है। विशेष तथ्य: 55.6% (जीडीपी का)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. 'वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र' एवं 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' के संदर्भ में, **'वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) (B) राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता (C) वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव (D) वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान (जीडीपी वित्त वर्ष 2026–27)'** (वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र) का सही 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' **वैश्विक मंदी व उच्च ब्याज दरों का दबाव** है। विशेष तथ्य: 6.8% से 7.2% (वित्त वर्ष 2026–27)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. 'वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र' एवं 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' के संदर्भ में, **'केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता (B) वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% (C) कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क (D) महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का) **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'केंद्र का प्रभावी पूँजीगत व्यय (प्रभावी पूँजीगत व्यय / जीडीपी)'** (वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र) का सही 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' **महामारी-पूर्व औसत: 2.7% (जीडीपी का)** है। विशेष तथ्य: 4.0% (जीडीपी का — वित्त वर्ष 2026 संकलन–25)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. 'वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र' एवं 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' के संदर्भ में, **'राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता (B) वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% (C) कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क (D) घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'राज्यों का पूँजीगत व्यय (' पूँजीगत व्यय / जीडीपी)'** (वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र) का सही 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' **राज्यों के पूँजीगत व्यय में अस्थिरता** है। विशेष तथ्य: 2.4% (जीडीपी का)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. 'वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र' एवं 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' के संदर्भ में, **'संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क (B) वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7% (C) घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान (D) नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'संघीय राजकोषीय घाटे में कटौती'** (वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र) का सही 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' **वित्त वर्ष 2020–21 में 9.2% तथा वित्त वर्ष 2021–22 में 6.7%** है। विशेष तथ्य: 4.8% (वित्त वर्ष 2026 संकलन–25) \ 4.4% (संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2025–26) \ 4.3% (बजट अनुमान वित्त वर्ष 2026–27)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. 'वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र' एवं 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' के संदर्भ में, **'उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान (B) नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध (C) कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क (D) 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'उल्टे शुल्क ढाँचे का समाधान'** (वृहद-आर्थिक संकेतक / क्षेत्र) का सही 'महामारी-पूर्व / पूर्ववर्ती आधार' **कच्चे माल पर तैयार माल से अधिक आयात शुल्क** है। विशेष तथ्य: सीमा शुल्क युक्तिकरण द्वारा सुधार। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध (B) 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार (C) अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया (D) घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'शेयर बायबैक कराधान (अंश पुनर्खरीद कर)'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **घरेलू शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय के रूप में कराधान** है। विशेष तथ्य: सभी शेयरधारकों हेतु 'पूँजीगत लाभ' (पूँजीगत लाभ) के रूप में कराधान; प्रवर्तकों (प्रवर्तकों) पर अतिरिक्त बायबैक कर। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध (B) 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार (C) अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया (D) 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'न्यूनतम वैकल्पिक कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एवं क्रेडिट सेट-ऑफ'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **नई कर व्यवस्था में संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध** है। विशेष तथ्य: न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर (कर) बनाने का प्रस्ताव; नई कर व्यवस्था में कर देयता के 1/4 तक न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट सेट-ऑफ की अनुमति। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया (B) 3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार (C) 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी (D) अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'कैंसर उपचार की दवाओं पर मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क)'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **3 दवाओं (ट्रैस्टुजुमाब, ओसिमर्टिनिब, दुरवालुमाब) पर छूट के बाद विस्तार** है। विशेष तथ्य: कैंसर रोगियों के लिए 17 जीवनरक्षक दवाओं/औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से पूर्ण छूट। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी (B) अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर (C) अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया (D) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम (सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली) एवं कार्गो विंडो'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **अलग-अलग विभागीय पोर्टल और बहु-स्तरीय निकासी प्रक्रिया** है। विशेष तथ्य: 2 वर्षों में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली का रोलआउट एवं कार्गो क्लीयरेंस हेतु एकल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 61. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख (C) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (D) 15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण एवं अनुदान'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **15वें वित्त आयोग में 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी** है। विशेष तथ्य: 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी यथावत स्वीकार; वित्त वर्ष 2026–27 हेतु राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ का वित्त आयोग अनुदान। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 62. 'कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान' एवं 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' के संदर्भ में, **'स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख (C) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (D) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'स्टार्टअप एंजेल टैक्स एवं विदेशी कंपनी कर दर'** (कर सुधार / राजकोषीय प्रावधान) का सही 'पूर्ववर्ती व्यवस्था / दर' **अनिवासी/घरेलू निवेश पर एंजेल टैक्स; विदेशी कंपनियों पर 40% कर** है। विशेष तथ्य: एंजेल टैक्स (धारा 56(सात-ख)) पूर्णतः समाप्त; विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटकर 35%। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 63. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख (C) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (D) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 **उत्तर: (B) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'मौद्रिक नीति समिति (मौद्रिक नीति समिति)'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यख** है। विशेष तथ्य: 6 सदस्य (3 आरबीआई आंतरिक + 3 सरकार द्वारा नामित बाह्य सदस्य); गवर्नर के पास निर्णायक मत। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 64. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 (C) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (D) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42** है। विशेष तथ्य: प्रत्येक बैंक को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित प्रतिशत केवल नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है (बैंकों को इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 65. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) (C) फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन (D) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 **उत्तर: (D) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24** है। विशेष तथ्य: बैंकों को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताएँ का निर्धारित भाग स्वयं के पास नकद, स्वर्ण या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 66. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) (C) फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन (D) ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) **उत्तर: (A) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'स्थायी जमा सुविधा (स्थायी जमा सुविधा)'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17** है। विशेष तथ्य: तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की निचली सीमा; संपार्श्विक-मुक्त तरलता अवशोषण उपकरण। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 67. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन (B) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर) (C) ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) (D) पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ **उत्तर: (B) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सीमांत स्थायी सुविधा (सीमांत स्थायी सुविधा) एवं बैंक दर'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 (बैंक दर)** है। विशेष तथ्य: तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की ऊपरी सीमा; एसएलआर कोटे में से ओवरनाइट आपात उधार। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 68. 'मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान' एवं 'वैधानिक आधार / धारा' के संदर्भ में, **'जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) (B) पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ (C) फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन (D) वाणिज्यिक बैंक: 40% \ **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'जहाज आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण में छूट'** (मौद्रिक उपकरण / नियामक प्रावधान) का सही 'वैधानिक आधार / धारा' **फेमा विदेशी मुद्रा विनियमन** है। विशेष तथ्य: शिपिंग पोत के आयात हेतु बिना बैंक गारंटी या स्टैंडबाय साख पत्र के अग्रिम विप्रेषण। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 69. 'नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल' एवं 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' के संदर्भ में, **'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ (B) वाणिज्यिक बैंक: 40% \ (C) पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ (D) ₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को) **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: न्यूनतम निवल मालियत'** (नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल) का सही 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' **₹100 करोड़ या अधिक (31 मार्च को)** है। विशेष तथ्य: ₹50 करोड़ या अधिक (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को)। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 70. 'नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल' एवं 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' के संदर्भ में, **'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ (B) वाणिज्यिक बैंक: 40% \ (C) पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ (D) टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंटरनेट बैंकिंग: लाभप्रदता शर्त'** (नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल) का सही 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' **पिछले 4 में से 3 वर्षों में तथा ठीक पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ** है। विशेष तथ्य: ठीक पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 71. 'नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल' एवं 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' के संदर्भ में, **'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ (B) वाणिज्यिक बैंक: 40% \ (C) टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती (D) ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण) कुल लक्ष्य'** (नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल) का सही 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' **वाणिज्यिक बैंक: 40%** \ है। विशेष तथ्य: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/लघु वित्त बैंक: 75% \। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 72. 'नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल' एवं 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' के संदर्भ में, **'उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती (B) ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान (C) पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ (D) प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'उद्गम (उद्गम) बनाम प्रवाह (प्रवाह) बनाम दक्ष (दक्ष)'** (नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल) का सही 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' **पृथक ऑफलाइन/विभागीय प्रक्रियाएँ** है। विशेष तथ्य: उद्गम: लावारिस जमा खोज पोर्टल \। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 73. 'नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल' एवं 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' के संदर्भ में, **'भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान (B) प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन (C) बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान (D) टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ)'** (नियामक मानदंड / बैंक श्रेणी / पोर्टल) का सही 'पूर्ववर्ती प्रावधान / लक्ष्य' **टियर-3 से टियर-6 केंद्रों व पूर्वोत्तर राज्यों में पीओएस/ तैनाती** है। विशेष तथ्य: अवधि दिसंबर 2025 तक विस्तारित; पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी पीआईडीएफ में शामिल किया गया। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 74. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान (B) प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन (C) बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान (D) एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'यूपीआई लाइट (यूपीआई लाइट)'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **ऑन-डिवाइस वॉलेट; कोर बैंकिंग सिस्टम पर लोड के बिना पिन-रहित भुगतान** है। विशेष तथ्य: प्रति लेन-देन: ₹1,000 से कम (₹1,000) \। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 75. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान (B) प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन (C) एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान (D) छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'यूपीआई सर्कल (यूपीआई सर्कल)'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **प्राथमिक उपयोगकर्ता द्वारा परिवार/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों को भुगतान अधिकार का प्रत्यायोजन** है। विशेष तथ्य: पूर्ण प्रत्यायोजन में: ₹15,000 मासिक एवं ₹5,000 प्रति लेन-देन। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान (B) छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान (C) बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान (D) 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'यूपीआई 123पे (यूपीआई 123पे)'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन के लिए यूपीआई भुगतान** है। विशेष तथ्य: प्रति लेन-देन सीमा: ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की गई। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान (B) 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर (C) अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) (D) एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'माई-यूपीआई (यूपीआई / यूपीआई सहायता 2.0)'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **एआई-संचालित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता-) यूपीआई ग्राहक सहायता और विवाद समाधान** है। विशेष तथ्य: 247 स्वचालित शिकायत निवारण और रीयल-टाइम ट्रैकिंग। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान (B) 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर (C) अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) (D) अनुच्छेद 279क एवं मानवीय उपभोग की शराब **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'यूपीआई व्यापार सक्षम एवं टैप एंड पे'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **छोटे व्यापारियों हेतु प्रोत्साहन योजना एवं पीओएस पर एनएफसी टैप भुगतान** है। विशेष तथ्य: छोटे व्यापारियों (लघु व्यापारियों) और संपर्क-रहित पीओएस भुगतानों पर केंद्रित। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. 'डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा' एवं 'मुख्य तकनीकी विशेषता' के संदर्भ में, **'मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) (B) 2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर (C) अनुच्छेद 279क एवं मानवीय उपभोग की शराब (D) जीएसटी अधिनियम की नई धारा 128क **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'मानक बनाम उच्च-मूल्य यूपीआई सीमाएँ'** (डिजिटल भुगतान उत्पाद / सुविधा) का सही 'मुख्य तकनीकी विशेषता' **2 एवं 2 रियल-टाइम फंड ट्रांसफर** है। विशेष तथ्य: सामान्य: ₹1 लाख \। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. 'जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र' एवं 'संवैधानिक अनुच्छेद / वैधानिक धारा' के संदर्भ में, **'जीएसटी परिषद की मतदान संरचना'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 279क एवं मानवीय उपभोग की शराब (B) जीएसटी अधिनियम की नई धारा 128क (C) अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016) (D) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआई) परिपत्र **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'जीएसटी परिषद की मतदान संरचना'** (जीएसटी प्रावधान / सुधार क्षेत्र) का सही 'संवैधानिक अनुच्छेद / वैधानिक धारा' **अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016)** है। विशेष तथ्य: गणपूर्ति: 50% \। (केंद्रीय बजट एवं आर्थिक समीक्षा पोर्टल एवं IUC Academy)